



जयपुर

मंगलवार

16 जुलाई, 2024

वर्ष: 10 अंक: 92

राजस्थान का सर्वाधिक ई-पेट दैनिक

अंदोलन नहीं अखबार

द पुलिस पोस्ट

जयपुर, जैसलमेर, भीलवाड़ा से प्रसारित

दूरभाष: 01482-45584 पृष्ठ: 08 मूल्य: 1.50 रुपये

खबर संक्षेप

नेपाल की विदेश सचिव ने मिसरी को बढ़ाई दी

काठमांडू। नेपाल की विदेश सचिव सेवा लमसल ने सोमवार को विक्रम मिसरी को भारत का



विदेश सचिव नियुक्त किए जाने पर बढ़ाई दी और कहा कि वह बहुआयामी नेपाल-भारत संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिये उत्सुक हैं। चीन और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों पर विशेषज्ञ माने जाने वाले अनुभवों राजनयिक विक्रम मिसरी ने सोमवार को भारत के नए विदेश सचिव का पदभार संभाल लिया। भारतीय विदेश सेवा के 1989 बैच के अधिकारी मिसरी ने विनय क्वात्रा का स्थान लिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने तलाक याचिका पर मांगा जवाब

जम्मू। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को



पत्नी पावल अब्दुल्ला को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह जवाब उमर अब्दुल्ला की तलाक वाली याचिका पर मांगा। उमर ने अपनी पत्नी से तलाक के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने याचिका पर पावल से छह सप्ताह के भीतर जवाब देने के लिए कहा है। उमर अब्दुल्ला की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि दंपति का विवाह मृत हो चुका है। क्योंकि दोनों पिछले 15 सालों से अलग-अलग रह रहे हैं।

सरपंचों को संतुष्ट करने की कवायद में जुटी भजनलाल सरकार

संघ की मांगों का परीक्षण कराने के लिए निर्देश

द पुलिस पोस्ट



जयपुर(कास.)। भजनलाल सरकार राजस्थान के सरपंचों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार उनके पांच विधानसभा सीटों पर उप चुनाव से पहले ही सौगात दे सकती हैं। इसके संकेत पंचायती राज व ग्रामीण विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अमर कुमार ने दे दिए हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राज को विकसित राज्य की श्रेणी में लाने और कर्मचारियों सहित आमजन को राहत देने के लिए प्रयासरत हैं और हाल ही में पेश किया गया बजट इसका जीता जागता उदाहरण है। पंचायती राज व ग्रामीण विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अमर कुमार ने सरपंच संघ की मांगों का उच्च स्तरीय परीक्षण कराने के निर्देश दिए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव व पंचायती राज विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने पंचायती राज, मनरेगा, वित्त, सार्वजनिक निर्माण, खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ सरपंच संघ की 14 सूत्रीय मांगों के

फाइल को रोककर रखना, भ्रष्टाचार का मुख्य कारण: मुख्य सचिव सुधांशु पंत

जयपुर (कास.)। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने कहा है कि फाइल को रोककर रखना भ्रष्टाचार का एक मुख्य कारण हो सकता है। एक फाइल का डिस्पोजल 24 मिनट में कर देता है। सुधांशु पंत बिड़ला सभागार में एसीबी के स्थापना दिवस के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा- जब मैंने पद ग्रहण किया था, उस समय सभी विभागों को फाइल डिस्पोजल टाइम करने के लिए कहा था। उस दौरान अधिकारियों को कुछ समय के लिए परेशानी हुई, लेकिन अब सब कुछ सही चल रहा है। सुधांशु

पंत ने कहा- सरकार के 68 विभागों में फाइल डिस्पोजल टाइम को लेकर एक डिपार्टमेंट मॉनिटरिंग कर रहा है। इसका परिणाम है कि जनवरी में मेरा फाइल डिस्पोजल टाइम जो 12 घंटे था, वह जून में 24 मिनट पर आ गया है। मुख्य सचिव ने कहा- फाइल को रोककर रखना भ्रष्टाचार का एक मुख्य कारण हो सकता है। इसलिए हमने ई-फाइल चालू की। चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के लेवल पर जनवरी में फाइल डिस्पोजल टाइम 22 घंटे 50 मिनट था।

शेख हसीना ने दुकराया चीन का 'ऑफर' बोली-

तीस्ता प्रोजेक्ट के लिए भारत पर जताया भरोसा चीन के आर्थिक मदद के जाल से देश को बचाया

एजेसी ॥ ढाका

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना हाल ही में चीन के दौरे पर गई थीं। उनके दौरे को लेकर कई तरह की चर्चाएं हुईं। कहा जाने लगा था कि चीन बांग्लादेश को लोन दे देगा। वो उसे अपने पाले में कर लेगा और भारत के सामने नई चुनौती खड़ी हो जाएगी, लेकिन ये सभी बातें धरी की धरी रह गईं। हुआ एकदम विपरीत।

शेख हसीना का चीन दौरा 4 दिन का था, लेकिन वह 3 दिन में ही देश वापस लौट गईं। यात्रा के दौरान चीन ने ऑफर दिया कि वह तीस्ता प्रोजेक्ट उनके साथ करें। इस पर शेख हसीना ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए उन्हें भारत पर ही भरोसा है। दरअसल, शेख हसीना इस उम्मीद के साथ चीन गई थीं कि शी जिनिपिंग उनको बहुत ज्यादा अहमियत देंगे। दरअसल, 2016 में जब जिनिपिंग बांग्लादेश गए थे तब उन्होंने कई वादे किए थे।

उन्होंने कहा था कि हम आपको लाखों करोड़ों का लोन देंगे। हम आपके यहां निवेश करेंगे, लेकिन तब चीन की तूती बोलती थी। 8 साल बाद यानी 2024 में चीन की स्थिति ठीक नहीं है। वह आर्थिक संकट से गुजर रहा है। जिनिपिंग के उन्हीं वादों को याद रखते हुए शेख हसीना चीन गई थीं।

बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना चीन के दौरे पर गई थीं। 5 साल बाद उनका ये दौरा हुआ। हालांकि तय समय से पहले ही शेख हसीना का दौरा खत्म हो गया। शेख हसीना को 4 दिन चीन में रहना था, लेकिन वह 3 दिन में लौट गईं। दरअसल, शेख हसीना जिन उम्मीदों के साथ चीन गई थीं, वैसे कुछ हो नहीं पाया और सम्मान के लिए उन्होंने चीन के ऑफर को भी ठुकरा दिया।



दुकराया 900 करोड़ का लोन ऑफर

शेख हसीना उम्मीद कर रही थीं कि चीन उन्हें 4 लाख करोड़ का लोन तो दे ही देगा। मगर चीन ने जो लोन ऑफर किया उसे जानकर बांग्लादेश हेरान था। चीन उसे 900 करोड़ का लोन ही ऑफर कर रहा था। बांग्लादेश टेरान था कि चीन की कथनी और करनी में इतना फर्क है। कहा जा रहा है कि शेख हसीना इससे नाखुश थीं और इन्होंने वजहों से उन्होंने यात्रा तय समय से पहले ही खत्म कर दी।

बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के मुताबिक, चीन से मिलने वाले ऑफर से ढाका खुश नहीं था, क्योंकि ढाका उपाय की उम्मीद कर रहा था। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को शी के साथ लंबी बातचीत की उम्मीद थी लेकिन केवल संक्षिप्त बातचीत ही हो पाई। इसके अलावा चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने शेख हसीना से मुलाकात तक नहीं की। यही नहीं, चीनी मीडिया ने भी शेख हसीना के दौरे को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया।

इस साल दो बार भारत आई शेख हसीना

चीन के दौरे से पहले बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भारत आई थीं। वह इस साल दो बार भारत का दौरा कर चुकी हैं। दोनों यात्राएं जून में हुईं। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुईं और बाद में द्विपक्षीय राजकीय यात्रा पर दिल्ली आईं। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद किसी विदेशी नेता की यह पहली यात्रा थी। वहीं, उन्होंने अखिरी बार जुलाई 2019 में चीन का दौरा किया था। चीन और बांग्लादेश के संबंध मधुर रहे हैं। लेकिन भारत और बांग्लादेश की बढ़ती नजदीकियों से चीन को निर्वी लग जाती है। बांग्लादेश को अपने पाले में करने के लिए ही वो उसे लोन देता है। चीन बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। हालांकि इससे पहले भारत के साथ ये जुड़ा था। उधर, कोरोना महामारी के बाद बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। शेख हसीना की सरकार उसे पटरी पर लाने का प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री चीन के दौरे पर गई थीं। उन्हें उम्मीद थी कि चीन उसे संकट से निकालने में मदद करेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। जानकार कहते हैं कि ढाका में भारत और चीन के प्रति संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखने की कोशिश की है। लेकिन नई दिल्ली की लगातार दो यात्राओं के साथ शेख हसीना ने भारत के प्रति झुकाव दिखाया है।

जलवायु परिवर्तन विश्व के लिए एक बड़ी चुनौती

प्राशांत महासागर में स्थित द्वीप हैं बड़े महासागरीय देश : जयशंकर

विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि हम सतत विकास की तलाश में प्राशांत द्वीप समूह का समर्थन करना अपनी जिम्मेदारी मानते हैं।



एजेसी ॥ नई दिल्ली

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को कहा कि भारत प्राशांत द्वीप समूह के विकास के प्रयासों का समर्थन करना अपनी जिम्मेदारी मानता है। उन्होंने कहा कि प्राशांत क्षेत्र के द्वीप छोटे द्वीप नहीं हैं, बल्कि बड़े महासागरीय देश हैं और भारत को उनका भागीदार बनने का अवसर मिला है।

विदेश मंत्री ने कहा कि हम सतत विकास की तलाश में प्राशांत द्वीप समूह का समर्थन करना अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं, गरीबी उन्मूलन और स्वास्थ्य सेवा आम चुनौतियां हैं, जिनसे हमें मिलकर निपटने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत अपने हिंद-प्राशांत साझेदारों के साथ और अधिक काम करने के लिए हमेशा

तैयार है। विदेश मंत्री ने यह बात डिजिटल माध्यम से हुए एक कार्यक्रम में कही हैं। इस कार्यक्रम में भारत ने मार्शल द्वीप में चार सामुदायिक विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए समझौते ज्ञान पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि इन परियोजनाओं में एलुक एटोल में एक सामुदायिक खेल केंद्र, मेजित द्वीप पर हवाई अड्डा टर्मिनल, अर्नो और वोदुजे एटोल में सामुदायिक केंद्र शामिल हैं। ये निश्चित रूप से मार्शल द्वीप के लोगों को बेहतर बुनियादी ढांचा प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत और मार्शल द्वीप गणराज्य के बीच मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों का एक लंबा इतिहास है। पिछले कुछ वर्षों में भारत-प्राशांत द्वीप समूह सहयोग मंच (एफआईपीआईसी) के तत्वाधान में विस्तार हुआ है।

ये सब हमारे सहयोग के मुख्य क्षेत्र हैं

विदेश मंत्री ने कहा कि मैं उन्हें हासिल करने की दिशा में प्रगति देखकर खुश हूँ। हम मार्शल द्वीप गणराज्य के लिए विलगनीकरण (पानी से नमक और अन्य खनिजों को अलग करने वाली) इकाइयों और डायलिसिस मशीनों के संबंध में प्रस्तावों पर भी काम कर रहे हैं। भारत प्राशांत द्वीप देशों की प्रथमिकताओं और जरूरतों को पहचानता है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल और संबंधित बुनियादी ढांचे, गुणवत्ता और सस्ती दवाएं, अच्छी जीवन शैली, उत्कृष्टता केंद्र, शिक्षा और क्षमता निर्माण, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र का विकास, नवीकरणीय ऊर्जा और स्वच्छ जल सुविधाएं ये सभी हमारे सहयोग के कुछ मुख्य क्षेत्र हैं।

सरकार कराएगी सर्वे, जयपुर से रोहिंग्या-घुसपैठियों को करेगी बाहर

द पुलिस पोस्ट

जयपुर(कास.)। सरकार ने राजधानी जयपुर में बाहरी लोगों की पहचान के लिए सर्वे कराने की तैयारी कर ली है। जयपुर में रोहिंग्या और घुसपैठियों को चिह्नित कर बाहर करने की तैयारी की जा रही है। दरअसल, जयपुर शहर में संचालित हटवाड़ों में व्यापार करने वालों और स्ट्रीट वेंडर्स को अब नगर निगम नए सिरे से पहचान करके लाइसेंस जारी करेगा। इसके लिए एक सर्वे करवाया जाएगा। इसमें इनकी पूरी जांच पड़ताल होगी। इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य बांग्लादेश और बर्मा से आए रोहिंग्या और घुसपैठियों को चिह्नित करके शहर से बाहर करना है। जयपुर नगर निगम गेट में फुटकर व्यवसाय पुनर्वास समिति बैठक में यह फैसला लिया गया। समिति सदस्यों ने बताया कि स्ट्रीट वेंडर्स स्वरोजगार के माध्यम से सरकार न केवल गरीबों को रोजगार दे रही है, बल्कि इससे उपभोक्ताओं को सस्ते दर पर सामान भी उपलब्ध हो रहा है। जयपुर शहर में हर रोज किसी न किसी परिचायक ने हटवाड़ा संचालित होता है। इसमें फुटकर व्यापारी आकर अपना व्यापार करते हैं। शिकायत मिल रही है कि यह हटवाड़े नगर निगम गेट की अनुमति के बिना संचालित हो रहे हैं। इन हटवाड़ों में बांग्लादेश, बर्मा से आए रोहिंग्या और दूसरे अवैध घुसपैठिए भी व्यापार करने लगे हैं। इससे यहां के



स्थानीय गरीब लोगों का हक खत्म हो रहा है। समिति ने बैठक करते हुए नगर निगम गेट परीचा में बिना निगम प्रशासन की एनओसी या मंजूरी के हटवाड़े संचालित नहीं करने का फैसला किया। इसके साथ ही इन हटवाड़ों में सर्वे करवाने और साथ ही शहर में स्ट्रीट वेंडर्स (थड़ी-ठेले) वालों का सर्वे करके उनका रिकार्ड तैयार करने का निर्णय किया। ताकि इनकी पहचान हो सके। इनका नाम वेंडर्स सूची में शामिल करके इनको लाइसेंस दिए जा सके। स्ट्रीट वेंडर्स के रूप में जयपुर में कई अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्या ने डेरा जमा रखा है। इन लोगों ने शहर के चौआड़पी क्षेत्र में सड़क और फुटपाथ पर मनमाने तरीके से कब्जा जमा रखा है। इससे ट्रैफिक जाम लगता है।

गोल्फ कोर्स-पोलो क्लब में बरशिप मामले में एसओजी करेगी जांच: झाबर सिंह खर्वा

द पुलिस पोस्ट

जयपुर(कास.)। जयपुर के सेंट्रल पार्क में बनाए गए रामबाग गोल्फ कोर्स और पोलो क्लब की सदस्यता देने के मामले की आज विधानसभा में गूँज रही। भाजपा विधायक कालीचरण सराफ ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए इस मुद्दे को उठाया। सराफ ने कांग्रेस सरकार के समय विधायक, यूडीएच और जेडीए के अधिकारियों को दो गैर-मैबरशिप पर सवाल खड़े किए। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्वा ने सदन में एसओजी से जांच करवाने की घोषणा की। सदन में विधायक सराफ ने कहा कि- यहां के सचिव और कैप्टन बिना क्लब के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को जानकारी दिए मैबरशिप दे रहे हैं। मनमानी फीस वसूल रहे हैं। विधायक ने बताया- 19 लाख, 29 लाख, 50 लाख रुपए लोगों से ले रहे हैं। ये किस आधार पर इतने पैसे ले रहे हैं। सराफ ने क्लब परिसर में संचालित गतिविधियों (बार, रेस्टोरेंट) पर भी सवाल उठाए। विधायक ने कहा कि जब जमीन को लेकर कोई एमओयू नहीं हुआ। जेडीए को कोई किराया नहीं दे रहे। इसके बावजूद भी कैसे यहां नया कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। हम उनसे कोई लीज या किराया नहीं ले रहे तो क्या सरकार या जेडीए ने उनको बार और रेस्टोरेंट संचालन की अनुमति दे रखी है?



यहां जो वित्तीय अनियमितताएं हैं, उसे दिखावाए। यहां जो लूट का रकबा रखा है। उसका खुलासा हो सके। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्वा ने कहा कि गोल्फ क्लब को दिल्ठी के गोल्फ क्लब की तर्ज पर संचालन करवाने की कार्यवाही की जाएगी। इस मामले में जो भी गड़बड़ी हुई है। इसकी जांच में एसओजी से करवाने की घोषणा करता हूँ। पूर्व यूडीएच मंत्री और विधायक शांति धारीवाल ने कहा- मैं खुद चाहता हूँ कि सरकार इस मामले की स्पष्ट जांच करवाए। जिस तरह पहले यूडीएच, जेडीए के अफसरों को मैबरशिप दी गई, उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन आप मेरी बात सुन लो। आप उन दोनों (गोल्फ क्लब, पोलो क्लब) का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे।

राहत की सौगात, आमजन के साथ भाजपा सरकार

जमीन के बदले अब ज्यादा मुआवजा देगी भजनलाल सरकार

15 की जगह 25 फीसदी जमीन दी जाएगी, कॉमर्शियल जमीन की जगह आवासीय का भी विकल्प

द पुलिस पोस्ट

जयपुर(कास.)। प्रदेश की भजनलाल सरकार आमजन को राहत देने के लिए कई घोषणाएं कर रही है। सरकार ने सड़क, बाइपास और मास्टर प्लान के लिए अधिग्रहित की गई जमीन पर अब ज्यादा मुआवजा देने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है कि 2005 से पहले के जिन केस में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो गई है या जमीन अधिग्रहण के बदले में मुआवजा देने का ऑर्डर जारी हो



चुका है, उनमें 10 फीसदी ज्यादा मुआवजा दिया जाएगा। राज्य सरकार के आदेश के तहत अब ऐसे केस में अधिग्रहित की जमीन का 15 फीसदी(विकसित भूमि) की जगह 25 फीसदी मुआवजा दिया जाएगा। वहीं, 2005 से पहले और इसके बाद के मामलों में भी मुआवजे में बदलाव किया गया है।

भूमि अवाप्ति(अधिग्रहण) के पुराने नियमों के तहत 2005 से पहले अधिग्रहित जमीन के बदले 15 फीसदी आवासीय जमीन का प्रावधान है, लेकिन सरकार अब अनिवार्य अवाप्ति के प्रावधान में मुआवजा 25 फीसदी देने जा रही है। इसमें 20 फीसदी आवासीय और 5 फीसदी कॉमर्शियल उपयोग की जमीन होगी। इसमें भी अगर कॉमर्शियल

जमीन उपलब्ध नहीं है या खातेदार पूरी जमीन आवासीय लेना चाहता है तो उसे 30 फीसदी जमीन मिलेगी। वहीं, साल 2005 के बाद के प्रकरण जिनमें अवाप्ति जारी हो चुका है और मुआवजा 25 फीसदी देना है। सरकार ने इन प्रकरणों में 25 फीसदी (20 फीसदी आवासीय, 5 फीसदी कॉमर्शियल) के स्थान पर 30 फीसदी जमीन देने का भी विकल्प दिया

है। बता दें कि किसी भी परिचायक में सेक्टर रोड, बाइपास या मास्टर प्लान की सड़क के लिए जमीन अवाप्ति की जाती है। उसे अनिवार्य अवाप्ति के तहत ली जाती है। इस तरह के अधिकांश अवाप्ति के प्रकरण प्रदेश की नगरीय निकायों में लंबित हैं। सरकार ने ऐसे प्रकरणों का जल्द डिस्पोजल करने के लिए ये नियम लागू किया है।

विभाग की ओर से हाल में ही एक भूमि अधिग्रहण के मुआवजे संबंधी आवंटन की नई शर्तें तय करते हुए आदेश जारी किए हैं। यह आदेश उन मामलों पर लागू होगा, जिनमें 27 अक्टूबर 2005 से पहले जमीन के मुआवजे का लेटर जारी हो चुका है, लेकिन जमीन को लेकर खातेदार से विवाद

होने के कारण उसका अब तक कब्जा नहीं लिया है। ऐसे प्रकरणों में सरकार अब नई शर्तें तय करते हुए आदेश जारी किए हैं। यह आदेश उन मामलों पर लागू होगा, जिनमें 27 अक्टूबर 2005 से पहले जमीन के मुआवजे का लेटर जारी हो चुका है, लेकिन जमीन को लेकर खातेदार से विवाद

शिवगंज का व्यापारिक गौरव वापस लाने के लिए चांदाना सर्विस रोड जरूरी

राजनीतिक के भेट चढा चांदाना सर्विस रोड अब मंजीजी लाना चाहतें है पर कांग्रेस वाले अड़ंगा लगा रहे है

शिवगंज शहर से चार किलोमीटर दूर फोरलेन का सर्विस रोड होने से व्यापार हुआ प्रभावित, पलायन को मजबूर हो रहे व्यापार

पालिका की ओर से चांदाना पुलिया तक निर्मित करवाया जा चुका है दो तरफा रोड़, लाईट की भी सुविधा है उपलब्ध ...

पालिका प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है ईस रोड पर पडी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हो रहा है बिलानाम भूमि से अतिक्रमण मुक्त करावे एक फिट लाखों रुपए है भाव

द पुलिस पोस्ट

शिवगंज। रियासत काल के दौरान आज से करीब 169 वर्ष पूर्व जब सिरौही के महाराव शिवसिंह ने अपनी रियासत के अंतिम छोर पर शिवगंज नगर की स्थापना की थी। उस समय उनका यह सपना था कि वे इस नगर को व्यापारिक नगरी के रूप में फलता फूलता देखें। उनका यह सपना पूरा भी हुआ। आज यह शहर पश्चिमी राजस्थान में प्रमुख व्यापारिक केन्द्र के नाम से पहचाना जाता है। इतना ही नहीं सुदूर प्रदेशों में तो इस शहर को मिनी मुंबई तक के नाम से पहचानते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों के दौरान या यूँ कहें कि जब से फोरलेन शहर के बाहर से निकला है तब से यहां का व्यापार भी काफी प्रभावित हुआ है। नतीजतन यहां के कई प्रमुख व्यापारियों ने अपना व्यवसाय अन्यत्र स्थापित करना शुरू कर दिया है। इसकी प्रमुख वजह शहर से कनेक्टिविटी की समस्या है। फोरलेन के लिए वन क्षेत्र से होकर करीब चार किलोमीटर की दूरी होने की वजह से यहां की ग्राहकी पर भारी असर हुआ है। इस समस्या के समाधान को लेकर शहर से आधा किलोमीटर की दूरी पर चांदाना पुलिया के समीप से सर्विस रोड बनाने को लेकर शहर के प्रमुख राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की ओर से पिछले तीन साल से राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सड़क परिवहन मंत्रालय से पत्र व्यवहार कर आग्रह किया गया है। मगर लंबा समय बीत जाने के बाद भी मंत्रालय से सर्विस रोड बनाने को लेकर हरी झंडी नहीं मिल सकी है।



गौरतलब है कि सिरौही जिले के इस प्रमुख व्यापारिक शहर का व्यापार उस समय तक बुलंदियों पर हुआ करता था। जब शहर के भीतर से होकर राजमार्ग गुजरता था। शैने शैने यातायात भार बढ़ जाने की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने फोरलेन निर्माण के फोरलेन बनाने की प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने के बाद व्यापारी खुश थे। वह इसलिए कि व्यापारियों को इस बात की उम्मीद थी कि फोरलेन बनने के बाद यहां का व्यापार और बढ़ेगा। लेकिन हुआ इसके विपरीत। शहर से बाहर होकर फोरलेन का निर्माण होने तथा शिवगंज से फोरलेन को जोड़ने के लिए करीब चार किलोमीटर दूर सर्विस रोड दे दिए जाने की वजह से आम जन व व्यापारियों को निराशा हाथ लगी। पहली बात तो यह कि यह चार किलोमीटर का क्षेत्र पूरा वन क्षेत्र है जहां रात के समय जंगली जानवरों का आना जाना रहता है। दूसरा यह कि पूरे मार्ग पर रात के समय घनघोर अंधेरा होने की वजह से रात के समय शहर में आने और जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा सुनसान क्षेत्र होने से लूटपाट का भी भय रहता है। इस वजह से धीरे धीरे शिवगंज का व्यापार प्रभावित होकर सुमेरपुर की तरफ परिवर्तित होने लगा। हालात यह हो गए कि आज सुमेरपुर में एक से बढ़कर एक बेहतरीन व प्रमुख ब्रांड की कंपनियों के शोरूम खुल गए हैं। जिसका असर शिवगंज के व्यापार पर पड़ा। परिणाम स्वरूप यहां के कई प्रमुख एवं प्रतिष्ठित व्यापारियों ने अपने व्यापार के पांव अन्य बड़े शहरों में जमाने शुरू कर दिए।

अब तक जा चुकी है दस जान

गौरतलब है कि शिवगंज शहर के आसपास में स्थित गांव कानपुरा, सलोदरिया, फतापुरा, कोरटा, बामनेरा, पोईना, गोला, बुढेरी, आल्पा, जोगपुरा, जोयला, रोवाडा, गोलिया सहित कई गांव हैं। इन गांवों में निवास करने वाले कई लोग प्रतिदिन यहां नौकरी या व्यापार करने अथवा अन्य किसी आवश्यक कार्य से शिवगंज आते हैं। शाम के समय अपना कार्य निबटाने के बाद वे जब अपने दुपहिया वाहनों से अपने घरों की तरफ लौटते हैं। उस समय सर्विस रोड नहीं होने की वजह से कई बार वे शॉर्ट कट के चक्कर में गलत दिशा से निकलने का प्रयास करते हैं। ऐसे में वे हादसे का शिकार हो जाते हैं। पुलिस विभाग के आंकड़ों पर नजर डालें तो अब तक इस मार्ग पर इस तरह के प्रयास में दस लोगों की जान जा चुकी है, जबकि सात से आठ लोग दुर्घटना में घायल होकर अंगभंग हो चुके हैं। बहरहाल, इस बार भी यह साल बीतने आया है, लोग आज भी इस उम्मीद में हैं कि इस बार तो उनकी इस मांग को पंख अवश्य मिलेंगे प्रशासन ध्यान नहीं दे रहे है ईस रोड पर सैकड़ों बिधा बिलानाम गोचर सहित अन्य सरकारी जमीन पर कब्जा हो गया है पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं शिवगंज से नजदीक सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने चाहिए नाडीओ व नालो गोचर की भूमि पर से अतिक्रमण मुक्त करवाकर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए

तीन साल पहले उठी मांग, चांदाना के समीप से हो सर्विस रोड

इस समस्या को लेकर आज से करीब तीन साल पहले व्यापारियों की ओर से शहर से आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित चांदाना पुलिया के पास से शिवगंज के लिए सर्विस रोड बनाने की मांग उठने लगी। इसे लेकर कई व्यापारिक संगठनों की ओर से राजमार्ग एवं सड़क परिवहन मंत्रालय से पत्र व्यवहार भी शुरू किया गया। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए यहां के प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों

ने भी राजमार्ग एवं सड़क परिवहन मंत्री नितीन गडकरी से मुलाकात एवं पत्र व्यवहार कर चांदाना के समीप से सर्विस रोड बनाने की मांग रखी मांग को मिली सफलता मगर नहीं मिली राहत हालांकि व्यापारिक संगठनों, राजनीतिक दलों व प्रबुद्ध जनों की ओर से की गई इस मांग को सफलता नहीं मिली। सड़क परिवहन मंत्रालय के मंत्री गडकरी की ओर से यहां के लोगों की मांग पूरी करने का आश्वासन भी मिला। उनके मंत्रालय से इससे संबंधित फाइल मुव भी हुई मगर आज तीन साल बीतने आए सर्विस रोड बनाने की स्वीकृति संबंधी

हरी झंडी अभी तक नहीं मिल पाई है। ऐसे में इस आशंका ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं कि यहां का व्यापार पूरी तरह से प्रभावित नहीं हो जाए। लोगों को अब इस बात की उम्मीद है कि प्रदेश और केन्द्र दोनों में भाजपा की सरकार है। ऐसे में अब इस सर्विस रोड का निर्माण संभव हो सकता है।

पालिका ने भी बनाया नया दो तरफा मार्ग

चांदाना के समीप से सर्विस रोड की कवायद शुरू होने के बाद आम नागरिकों की मांग पर पालिका



प्रशासन ने भी शिवगंज के क्रांति चौराहे से लेकर चांदाना पुलिया तक दो तरफा चौड़ मार्ग तैयार करवाया है। इसके अलावा सड़क के बीच डिवाइडर बनाकर वहां रोशनी के लिए भी व्यवस्था की है।

सीएलजी की मितिंग मे शहर में खुल्ले आम बिक रहा एमडी नशे के विरुद्ध कारवाई की माँग उठीं

शहर मे सबसे ज्यादा नशा एमडी गांजा अफीम खुल्ले आम मिल रहा है

द पुलिस पोस्ट

शिवगंज थाना परिसर में मोहरम पर्व को लेकर सीएलजी की बैठक आयोजित की गई पुलिस थाना अधिकारी बाबूलाल राणा नगरपालिका सफाई निरीक्षक नरेश कुमार डगी वह शहर के गणमान्य नागरिक सहित पत्रकार कुछ नेतागण उपस्थित रहे सीएलजी की मितिंग को लेकर आए दिन अलग-अलग बातें होती रहती हैं कोई पर्व को लेकर कोई कुछ को लेकर पर ज्यादातर बातें होती हैं शहर में पनप रहों नशा क्योंकि शिवगंज शहर में सबसे ज्यादा एमडी नामक नशा सबसे ज्यादा बिक रहा है यह बातें और मितिंग में उठ रही है पर पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही शहर की मानी हुई सिटी जो कभी मिनी मुंबई के नाम से पहचानी जाती थी आज नशा का कारोबार सबसे ज्यादा हावी हो रहा है शहर की न्यू बस स्टैंड तहसील रोड केलेखर मंदिर के पीछे पुराना बस स्टैंड पर कॉलेज रोड पर अंबिका चौक में वह आखरीया चौक में सबसे ज्यादा एमडी मिल रही है बेचने वाले स्थानीय पड़ोसी सुमेरपुर से आते हैं यहां के बच्चों को देकर चले जाते हैं

शहर के धन्ना सैठो के बच्चे गरीबों को पहले फोगट मे खिलाओ फिर नशे के आदी होने के बाद वह घर बर्बाद हो जाएंगा



स्थानीय बच्चे बिगड़ रहे मां-बाप को तो पता ही नहीं चलता कि हमारा बच्चा कोई नशा कर रहा है क्योंकि एमडी का नशा गुटखो के साथ में लिया जाता है उनके परिवार को सिर्फ इतना ही पता चलता है कि हमारा बेटा गुटखा खाना चालू कर दिया पर उसका परिवार खत्म कर रहा है वह बच्चा पहले तो पैसा मांग के ले लेगा मांगने से नहीं मिलेगा तब चोरीया करेगा घर के गहने बेचेगा फिर इधर-उधर बड़ी घटना करेगा हो सकता है कभी बड़ी घटना भी कर सकता है क्योंकि नशा का कारोबार

ही ऐसा है बेचने वाले अमीर हो रहे है और नशा करने वाले बर्बाद इस सीएलजी की मितिंग में सबसे ज्यादा बात यही होती एमडी नशे को खत्म करना पुलिस मुखबिर तनज को मजबूत करना फिर मितिंग में महेंद्र कुमार दवे नरेंद्र कुमार जैन अब्बास अली भरत प्रजापति महादेव महिला मंडल अध्यक्ष उषा सोनी कोमल परिहार हिरल मांगने से नहीं मिलेगा तब चोरीया करेगा घर के गहने बेचेगा फिर इधर-उधर बड़ी घटना करेगा हो सकता है कभी बड़ी घटना भी कर सकता है क्योंकि नशा का कारोबार

6 साल के बेटे की हत्या कर सुसाइड किया: सब्जी गर्म करने को लेकर पति से हुआ था झगड़ा; चौथ माता के दर्शन करके आए थे

द पुलिस पोस्ट

सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में एक महिला ने 6 साल के बेटे की हत्या कर फंदे से लटक कर सुसाइड कर लिया। घटना बरवाड़ा थाना क्षेत्र के चौथ के बरवाड़ा कस्बे के ब्रह्मपुरी मोहल्ला में रविवार रात करीब 8:30 बजे की है। सीओ ग्रामीण घनश्याम वर्मा ने बताया- रोशनी देवी (28) और उसके पति विनोद (32) के बीच सब्जी गर्म करने की बात को लेकर झगड़ा हुआ था। इसके बाद विनोद बाजार चला गया था। घर में रोशनी और बेटा सचिन ही थे। रोशनी ने पहले चुन्नी का फंदा बनाकर बेटे को लटकाया और फिर खुद ने सुसाइड कर लिया। जब विनोद वापस आया तो दरवाजे खुले हुए थे। वह अंदर गया तो पत्नी और बेटे के शव फंदे से लटके मिले। वह चिल्लाया। इस दौरान आस-पास के लोग भी आ गए और दोनों को फंदे से उतारा। अचेत अवस्था में रोशनी और सचिन को कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस को हादसे की



रोशनी देवी (मां)

सचिन (बेटा)

सूचना देर रात मिली थी। सोमवार सुबह मौके पर पहुंचे। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि हादसे से कुछ देर पहले ही रोशनी चौथ माता के दर्शन करके आई थी।

चौथ का बरवाड़ा माता के दर्शन करके आया था परिवार

स्थानीय लोगों ने बताया कि परिवार में किसी तरह की अनबन नहीं थी।

रविवार शाम करीब 7 बजे पूरा परिवार चौथ का बरवाड़ा माताजी के दर्शन करके आया था। यहां मोहल्ले की महिलाओं को देख रोशनी ने बातचीत भी की थी। बातचीत में भी ऐसा नहीं लग रहा था कि रोशनी और उसका परिवार किसी बात को लेकर परेशान है। इसके बाद विनोद पत्नी और बच्चे को घर के बाहर छोड़ बाजार चला गया। गांव के

लोगों ने बताया कि विनोद के दो और भाई हैं। विनोद सबसे बड़ा है। तीनों भाई माता-पिता से अलग रहते हैं। सभी के अलग-अलग मकान हैं। विनोद मेडिकल की शॉप पर काम करता है। रोशनी का पीहर मलारना डूंगर तहसील के बड़ोलास गांव में है। रोशनी की छोटी बहन मोनिका की शादी विनोद के छोटे भाई दीपू से हुई है। वहीं, सचिन स्कूल नहीं जाता था।

पति बोला- तकरार के बाद घर से बाहर आ गया था

सीओ ग्रामीण घनश्याम वर्मा ने बताया- पूछताछ में विनोद ने बताया कि मंदिर दर्शन कर आने के बाद मैंने रोशनी से कहा था कि सब्जी गर्म कर देना। जवाब में रोशनी ने कहा था- ऐसे ही खा लो। इस पर मैं यह कहकर वहां से निकल गया कि धूप में रख देना। इसी बात से रोशनी नाराज हो गई और यह कदम उठा लिया।

रूस और ऑस्ट्रिया की यात्राओं से भारत की नई उड़ान



ललित गर्ग

भारत पर दुनिया का बढ़ता भरोसा इस बात का परिचायक है कि भारत विश्व की एक महाबड़ी शक्ति बनने की राह पर अग्रसर है और भारत शांति एवं अयुद्ध का हिमायती है। हम तो पहले ही यह कह चुके हैं कि भारत बुद्ध-महावीर-गांधी का देश है और इसकी विदेश नीति भी इनसे प्रेरणा लेकर ही तय होती रही है। बदलते वैश्विक सन्दर्भों के बावजूद भारत आपसी शान्ति, अहिंसा, युद्धमुक्त विश्व-संरचना व सह अस्तित्व पर ही विश्वास रखता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा के निष्कर्षों के साथ-साथ इसके वैश्विक निहितार्थ भी तलाशे जा रहे हैं। इन दोनों देशों की राजकीय यात्रा अनेक दृष्टियों से नई उम्मीदों को पंख लगाने के साथ भारत को शक्तिशाली बनाने वाली होगी। दोनों देशों की यात्रा के दौरान हुए विभिन्न समझौते भारत की तकनीकी एवं सामरिक जरूरतों को पूरा करने में अहम कदम साबित होंगे। सैन्य उत्पाद, व्यापार व उद्योग के साथ-साथ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रूस और ऑस्ट्रिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग ने नई उम्मीदें जगाई हैं। इन यात्राओं के दौरान प्रधानमंत्री ने जो प्रयास किए वे मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भरता के प्रयास, नये भारत-सशक्त भारत एवं सतत विकास की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होंगे। निश्चित ही प्रधानमंत्री मोदी के प्रति इन दोनों देशों में जो सम्मानभावना देखने को मिली, उससे यही कहा जा सकता है कि मोदी विश्व-नेता के रूप में स्वतंत्र पहचान एवं प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहे हैं, जो भारत के लिये शुभ है।



निश्चित तौर पर वैश्विक राजनीति में अपनी चमक के साथ आगे बढ़ते भारत के लिये रूस की यात्रा कई मायनों में बहुत उपयोगी एवं दूरगामी रही। इस यात्रा के दौरान भारत और रूस के बीच हुई 22वीं द्विपक्षीय बैठक में हुए नए समझौते काफी अहम हैं। रूस के युद्ध में फंसे होने के कारण रक्षा जरूरतों से संबंधित आपूर्ति में बाधा होना हमारे लिए चिंता की बात थी लेकिन मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही रक्षा उपकरणों के स्पेयर पार्ट्स का प्लांट लगाने पर सहमति जताकर पुनित ने बड़ी चिंता का समाधान कर दिया है। दोनों देशों के बीच का व्यापार 2030 तक 65 अरब डॉलर से बढ़कर 100 अरब डॉलर तक करने पर भी सहमति बनी है। यह भारत-रूस के विशेष रिश्ते को और मजबूत करने वाले होंगे। भारत-रूस की दोस्ती की गर्माहट से चीन एवं पाकिस्तान की बौखलाहट भी देखने को मिली है।

यूक्रेन और गाजा में युद्धों की पृष्ठभूमि के बीच प्रधानमंत्री मोदी की रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा पर दुनिया की नजरे लगी रही। एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रहे अमेरिका और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में अपना हित देख रहे रूस के बीच भारत की स्थिति एवं उसकी बढ़ती ताकत का भी विश्लेषण किया जा रहा है। मास्को में प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के गले मिलने पर यूक्रेन की नाराजगी के बावजूद अमेरिका की सधी प्रतिक्रिया सामने आती है इससे उसके भारत से रिश्ते पर कोई असर नहीं होगा। निश्चित ही इससे यह साफ हो जाता है कि दुनिया अब एक या दो ध्रुवीय नहीं रही।

संपादकीय

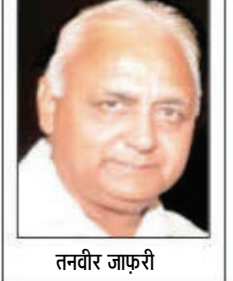
एनडीए को झटका

देश के सात राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के शनिवार को आए नतीजों में 'इंडिया' गठबंधन के घटक दलों ने भाजपा को करारा झटका देते हुए 10 सीटें जीती लीं। भाजपा दो सीट ही जीत सकी जबकि एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई। पश्चिम बंगाल की चार हिमाचल प्रदेश की तीन उत्तराखंड की दो, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु की एक-एक सीट के लिए चुनाव हुआ था। इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस 'आप', टीएमसी और द्रमुक ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। नतीजों से इंडिया गठबंधन के घटक दल गदर हैं, और कांग्रेस अध्यक्ष महिषाजित खरगे ने नतीजों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए दावा कि लोगों ने भाजपा के अहंकार कुशासन और नकारात्मक राजनीति को नकार दिया है और नतीजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की गिरती राजनीतिक साख का प्रमाण हैं। खरगे ने 'एक्स' पर पोस्ट करके इन नतीजों पर मतदाताओं का आभार जताया है। खास बात यह रही कि उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब में जनता ने पाला बदलने वाले नेताओं को नकार दिया। उत्तराखंड की दोनों सीटें कांग्रेस ने जीत लीं। सर्वाधिक चर्चा प्रसिद्ध तीर्थस्थल बद्रीनाथ सीट की है, जहां कांग्रेस अपनी सीट बरकरार रखने में सफल रही। यहां भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़े राजेंद्र सिंह भंडारी कांग्रेस के सिटिंग विधायक थे लेकिन पाला बदल कर भाजपा में जा मिले। भाजपा ने उन्हें प्रत्याशी बना दिया लेकिन कांग्रेस के लक्ष्मण सिंह बट्टोला ने उन्हें पराजित कर दिया। हिमाचल प्रदेश में भी रोचक परिदृश्य उभरा है। देहरा सीट से मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की पत्नी कमलेशा जीतीं। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी को हराया। प्रदेश में पहली बार होगा जब पति-पत्नी सदन में साथ होंगे। कांग्रेस के विधायक 40 हो गए हैं जबकि भाजपा की 28 सीटें हैं। फरवरी में राज्य सभा चुनाव के वक्त विधायकों की बनावट से कांग्रेस की सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे थे जो टल गया है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के गढ़ माने जाने वाले छिंदवाड़ा क्षेत्र में भाजपा ने कांग्रेस को फिर झटका देते हुए अमरवाड़ा सीट जीत ली। पश्चिम बंगाल में दीदी का जलवा कायम है, और टीएमसी ने चारों सीटें जीत लीं। भाजपा से तीन सीटें छीनी हैं। बेशक, नतीजे भाजपा के लिए खतरे की घंटी हैं, जिनका अर्थ में विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव तथा हरियाणा महाराष्ट्र और झारखंड के आसन्न असेंबली चुनाव पर निश्चित असर दिखेगा।

चिंतन-मन

कर्तव्य को बनाए सर्वोपरि लक्ष्य

अध्यापक ने विद्यार्थियों से पूछा- 'रामायण और महाभारत में क्या अंतर है?' विद्यार्थियों ने अपनी-अपनी समझ के अनुसार उत्तर दिए। अध्यापक को संतोष नहीं हुआ। एक विद्यार्थी ने अनुरोध किया- 'आप ही बताइए' अध्यापक बोला-रामायण और महाभारत में सबसे बड़ा अंतर है 'हक-हकूक' का। रामायण में राम ने अपना अधिकार छोड़ा, राज्य छोड़ा और चौदह वर्षों तक वन में जाकर रहें। वे चाहते तो अधिकार के लिए लड़ाई कर सकते थे। दशरथ उन्हें वन में नहीं भेजना चाहते थे। अयोध्या की जनता उनके वन-गमन से व्यथित थी। पर राम ने अपने कर्तव्य को अधिकार से ऊपर रखा। पिता के कहे का पालन उनके जीवन का महान आदर्श था। महाभारत का संपूर्ण कथानक अधिकारों की लड़ाई का कथानक है। कौरव और पांडव आस-से चचेरे भाई थे। भाई-भाई के रिश्तों में जो गंध होती है, मिथस होती है, अपनापा होता है, उसका दर्शन ही वहां कहां होता है। पांडव सब कुछ जुए में हार गए। सब वादे पूरे कर वे लौटे तो दुर्योधन ने पांच गांव तो वना, सूई की नोक के बराबर भूमि भी देने से मना कर दिया। ये दो उदाहरण हैं-हमारे सामने। प्रथम उदाहरण अपनेपन से भरे आत्मीय संबंधों का है। यह संबंधों की मधुरता व्यक्ति को कभी आत्मकेंद्रित नहीं होने देती। वह अपने बारे में नहीं सोचता; परिवार, समाज और देश के बारे में सोचता है। उसका अपना कोई स्वार्थ होता ही नहीं। पद-प्रतिष्ठा और सुख-सुविधा के संस्कारों से वह ऊपर उठ जाता है। ऐसा वही व्यक्ति कर सकता है, जो कर्तव्य को अपने जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य मानता है। वह संस्कृति सफल होती है जो कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तियों को जन्म देती है। वह शताब्दी सफल होती है, जो कर्तव्य की धारा को सतत प्रवाही बनाकर जन-जन तक पहुंचाती है। वह परंपरा सफल होती है, जो कर्तव्य का बोध देती है। आज आवश्यकता इस बात की है कि पूजा-प्रतिष्ठा, मान-सम्मान और सुख-सुविधा की अर्थहीन चिंता छोड़कर व्यक्ति अपने जीवन को कर्तव्य के लिए समर्पित करे।



तनवीर जाफ़री

आपातकाल विमर्श यानी गड़े मुर्दे उखाड़ना ?

6 वर्षों तक उनके चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी थी। उसके बाद ही जयप्रकाश नारायण द्वारा इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग को लेकर संपूर्ण क्रांति के नाम से राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ दिया गया था और देश भर में प्रदर्शन शुरू हो गए थे। हालांकि 24 जून, 1975 को जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो वहां भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के फ़ैसले को तो ज़रूर बरकरार रखा गया परन्तु इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बने रहने की इजाजत दे दी गई। उसके बावजूद अपना पद खोने के भय से इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा कर डाली। हालांकि कहा यह जाता है कि पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रॉय ने उस समय आपातकाल की घोषणा के निर्णय में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और आपातकाल का निर्णय दरअसल रॉय का ही निर्णय था। रॉय के फ़ैसले पर ही इंदिरा गांधी ने हामी भरी और उन्हीं की सलाह पर उसे लागू भी किया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी अपनी एक किताब में भी लिख चुके हैं कि 'वास्तव में इंदिरा गांधी ने मुझे बाद में बताया कि उन्हें आपातकाल की घोषणा के लिए संवैधानिक प्रवधानों की जानकारी भी नहीं थी'। अब यदि हम आपातकाल से ठीक पहले यानी 1974-75 के दौर को याद करें तो वह रेल आंदोलन, चक्रा जाम, तालाबंदी और राष्ट्रव्यापी धरने, प्रदर्शनों का दौर था। इसी दौरान 2 जनवरी 1975 को रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा की हत्या समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर उस समय कर दी गयी थी जब वे समस्तीपुर- दरभंगा ब्रॉड गेज रेलवे लाइन प्रारम्भ करने की घोषणा सम्बन्धी एक कार्यक्रम में वहां एक मंच पर मौजूद थे। यहां हुये एक शक्तिशाली बम विस्फोट में वे गंभीर रूप से घायल हो गए बाद में अगले दिन दानापुर के रेलवे अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद देश की

किसी सबसे बड़ी राजनैतिक हस्तों की यह दूसरी हत्या थी। इन्हीं विषय परिस्थितियों में 25 जून, 1975 को राष्ट्रपति फख्रुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान की धारा 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर डाली। आपातकाल के दौरान चुनाव स्थगित हो गए थे तथा नागरिक अधिकारों को समाप्त करके मनमानी की गई थी। और हर छह महीने बाद 1977 तक आपातकाल की अवधि बढ़ाई जाती रही। प्रेस पर सेंसरशिप लागू गयी थी। बाद में 18 जनवरी, 1977 को इंदिरा गांधी ने लोकसभा भंग करने और मार्च 77 में ही आम चुनाव कराये जाने की घोषणा करते हुये आपातकाल के दौर में जेलों में बंद किये गये सभी नेताओं को रिहा कर दिया। और 23 मार्च, 1977 को आपातकाल समाप्त करने की घोषणा कर दी गयी। परन्तु सवाल तो यह है कि 50 वर्ष पूर्व के उस इतिहास को आज और इस समय खंगालने की जरूरत भाजपा को क्यों महसूस हुयी ? 2014 से सत्ता में रहते हुये पिछले दस वर्षों में मोदी सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनावे का फ़ैसला क्यों नहीं लिया? और एक सवाल यह भी कि यदि देश की जनता आपातकाल से इतना ही दुखी थी और इंदिरा गांधी की तानाशाही से वास्तव में तंग आ चुकी थी तो उसी देश की जनता ने मात्र ढाई वर्ष बाद 1979 में इंदिरा गांधी को पुनः सत्ता क्यों सौंपी ? जिस दर्द को मुझे भर भुक्तभोगी नेता शायद सिर्फ इस्लिये याद कर रहे हैं कि 19 महीनों के मीसा काल में उन्हें जेलों में डाल दिया गया, कुछ पर अत्याचार किया गया, उनके निजी स्वतंत्र जीवन के एंश आराम को भाग किया गया, उसी दर्द को दुष्ट की जनता ढाई वर्षों में ही कैसे भुला बेठी ? बल्कि 1977 में लोकसभा चुनाव में पराजित होने के केवल एक वर्ष में ही जनवर, 1978 में इंदिरा इंदिरा गांधी ने चिकमंगलूर लोकसभा उपचुनाव में 77,333 मतों के

अंतर से जीत कर अपनी लोकप्रियता का लोहा मनवाया ? तो जब देश की जनता ने कांग्रेस के ऊपर आपातकाल का मतलब संविधान की हत्या का लेबल नहीं चिपकाया तो भाजपा नेता आखिर किस साजिश के तहत सत्ता में आने के पक्ष पक्ष बाद 50 वर्ष पुराने उस गड़े मुर्दे को उखाड़ रहे हैं जिसे देश भुला चुका है ? दरअसल भाजपा इस समय विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की संविधान बचाओ-देश बचाओ मुहिम से घबराया हुआ है। उसे यह एहसास हो चुका है कि देश की जनता ने कई भाजपा नेताओं द्वारा सार्वजनिक रूप से बोले जा रहे संविधान विरोधी बयानों को गंभीरता से लिया है और ऐसे कई उम्मीदवारों को पराजित भी किया है। विपक्ष की संविधान बचाओ की इसी सफल मुहिम ने भाजपा को 2019 में हासिल 303 सीटों से घटकर 240 तक पहुंचा दिया है। इसी चुनाव परिणाम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने तीसरे कार्यकाल में संसद में प्रवेश के पहले ही दिन संविधान को भांसे से लगाने का प्रदर्शन करने पर मजबूर किया। आपातकाल का एक पक्ष यह भी कि उस दौरान देश के सभी सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की समय पर हाजिरी हो रही थी। टेनें बसें सब समायानुसार सुचारु रूप से संचालित हो रही थीं। आम जनता को इससे लाभ मिल रहा था। इन सबके बावजूद जब कांग्रेस के सभी आला नेताओं ने आपातकाल के अपने ही फ़ैसले को गुलत स्वीकार कर लिया फिर इस बहस को तो बंद हो जाना चाहिये ? परन्तु अपने ऊपर लग चुके संविधान विरोधी होने के आरोपों से बचने के लिये भाजपा 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनावे का फ़ैसला लेने सम्बन्धी अधिसूचना जारी कर व इस पर विमर्श कर केवल गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश कर रही है।

मुद्दा: जनसंख्या समस्या और समाधान



अफ्रीका आदि क्षेत्रों में लोग भूख से क्यों मरते? निश्चय ही हमारा देश विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। हमने इस मैदान में चीन को भी पछड़ दिया है, और आज एक अरब 45 लाख से अधिक आबादी का बोझ उठा रहे हैं। बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण तथा अपराध में वृद्धि का यह भी कारण है कि भविष्य में भारत भी देश में बढ़ती सांप्रदायिकता और घृणा का एक बड़ा कारण भी जनसंख्या में वृद्धि है। बहुसंख्यक हिन्दू आबादी मुसलमानों की बढ़ती आबादी को खतरा मानती है। उनमें से कुछ का यह भी मानना है कि भविष्य में भारत भी पाकिस्तान की भांति इस्लामी राष्ट्र बन सकता है। यद्यपि यह कार्पनिक भविष्यवाणी है क्योंकि देश में मुसलमानों में भी बच्चों की जन्म दर कम हुई है परंतु हिन्दुओं में यह दर अधिक कम हुई है। कई अदूरदर्शी मतांती तथा मुस्लिम

नेता ही जनसंख्या रोकने के लिए कड़े कानून का विरोध करके हिन्दुओं की आंशका को मजबूत करते हैं। भाजपा सहित सच परिवार के सभी संगठन तथा उदारवादी मुसलमान जनसंख्या नियंत्रण कानून के पक्षधर हैं परंतु इस तथ्य की भी अवहेलना नहीं की जा सकती कि उच्च और मध्यम वर्ग के हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन के परिवार साधारणतया दो या तीन बच्चों तक सीमित होते हैं क्योंकि उन्हें अपने बालकों को उत्तम शिक्षा दिला कर सफल नागरिक बनाना होता है उन्हें पौष्टिक भोजन तथा साफ-सुथरा घर और वस्त्र उपलब्ध करने होते हैं जबकि निम्न वर्ग के लोग चूकित अशिक्षित या अर्धशिक्षित होते हैं, और उनके लिए मनोरंजन का एकमात्र साधन सैक्स होता है। अतः वे अधिक बच्चे पैदा करते हैं तथा उन्हें उनकी शिक्षा दीक्षा की चिंता नहीं होती

अपितु वे अपने आठ दस वर्ष के बालक को किसी ढाबे पर काम पर लगा देते हैं, और बालक आतथक रूप से आत्मनिर्भर हो जाता है। चूंकि मुसलमान, दलित और आदिवासी ही अधिकतर गरीब और आतथक-सामाजिक रूप से पिछड़े होते हैं, इसलिए उनके ही अधिक बच्चे होते हैं। निस्संदेह मोदी सरकार को कठोर जनसंख्या कानून बनाना चाहिए परंतु कटु सत्य यह भी है कि संसद में ऐसा सख्त कानून पास कराना कठिन होगा क्योंकि मौजूदा संसद में भाजपा के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। इसलिए कोई कानून पास कराने के लिए उसे सहयोगी दलों विशेष रूप से जुद्ध और टीडीपी का समर्थन लेना होगा परंतु दोनों दल मुस्लिम और दलित वोट को श्रेष्ठ में रखते हुए कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून को शायद समर्थन न दें। इसलिए इस कानून को भाजपा शासित प्रदेशों उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम, झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़ आदि की विधानसभाओं में पास कराकर सख्ती से लागू कराना होगा। प्रावधान करना होगा कि कानून लागू होने के बाद राशन कार्ड केवल चार व्यक्तियों यानी माता पिता व दो बच्चों का ही बनेगा और दो बच्चों को जन्म देने के पश्चात पति या पत्नी में से किसी एक को नसबंदी करानी होगी अथवा लिखित में सरकार को आश्वासन देना होगा कि भविष्य में तीसरा बालक पैदा नहीं करेंगे। तीसरा बच्चा पैदा करने वाले माता-पिता को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा। वैसे राजस्थान में कानून है कि दो से अधिक बच्चों वाले माता-पिता को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। केंद्र सरकार को यह कानून तो बनाना ही चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रति दिन सुबह, दोपहर और रात्रि में दस सेकंड का परिवार नियोजन से संबंधित सरकार द्वारा तैयार किया हुआ विज्ञापन आवश्यक रूप से दिखाए तथा हर भाषा के दैनिक अखबार को परिवार नियोजन का विज्ञापन अनिवार्य रूप से प्रकाशित करना होगा।



डॉ. असद रजा

जुलाई 12 से 31 तक विश्व में विशेष रूप से हमारे देश में जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा मनाया जा रहा है जिसमें जनसंख्या को बढ़ने से रोकने के लिए जागरूकता रैलियां निकाली जा रही हैं। जनसंख्या वृद्धि की समस्या के समाधान के बारे में विभिन्न राजनीतिक दलों के बयान आए हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह तथा भाजपा बिहार के राज्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि वह कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए परंतु एनडीए के घटक दल जदयू के नेता इस बारे में कठोर कानून बनाने का समर्थन नहीं करते क्योंकि उन्हें दलित और मुस्लिम मतदाताओं के बिदकने का भय है। वास्तव में जदयू और टीडीपी जैसे मोदी सरकार के घटक दलों को चिंता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन करने से उनका मुस्लिम और दलित वोट खिसक सकता है। इसलिए ये दल परिवार नियोजन के लिए जन-जागरूकता पर बल देते हैं। कुछ अति धर्मभीरू और मजहबी लोग बच्चों को अल्लाह की देन समझते हैं। मानते हैं कि अन्न-भोजन देने की जिम्मेदारी अल्लाह ने ले रखी है। इसलिए जनसंख्या को रोकने के लिए कठोर कानून की जरूरत नहीं है परंतु यह तर्क नहीं, कुतर्क है। ऐसा होता तो

नगरपालिका वह पैराफैरी क्षेत्र में मास्टर प्लान रिंग रोड पर नियमों के विपरीत अवैध रिसोर्ट निर्माण हो रहे हैं

रिंग रोड पर बन रही मुख्यमंत्री जन आवास योजना धन्ना सैठो की कॉलोनीया व प्लेट रोड पर कांटे जा रहे हैं

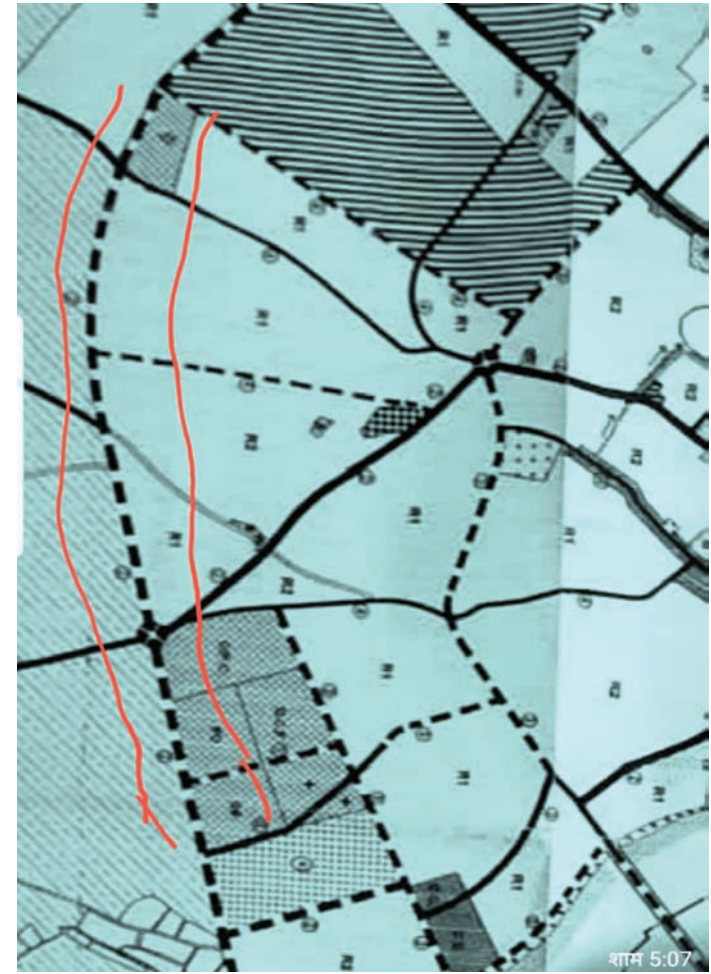
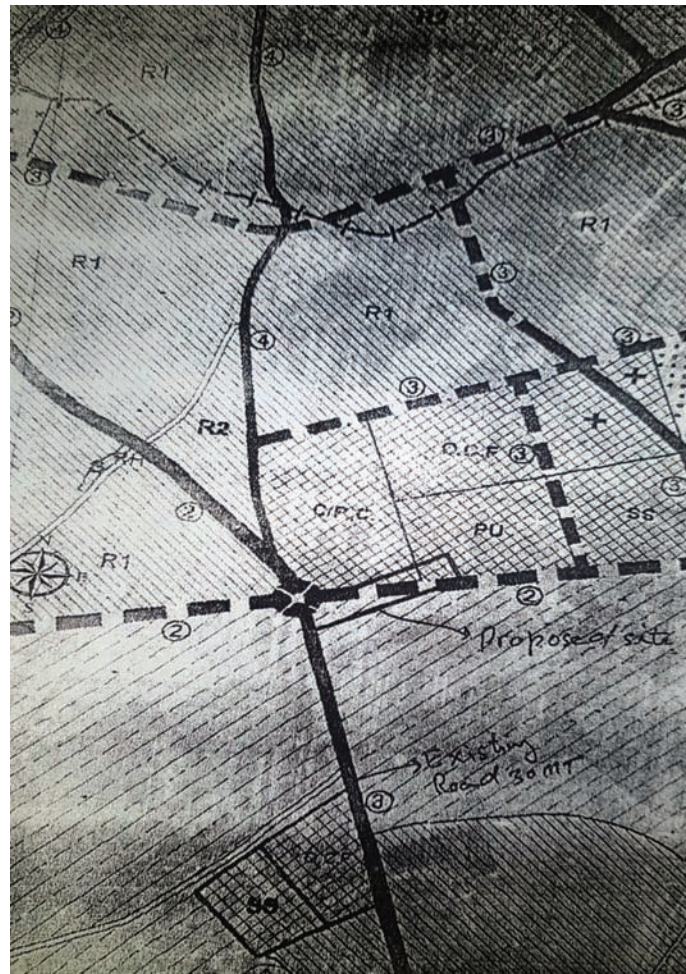
पालिका प्रशासन के अधिकारी व नगर नियोजक अधिकारियों की मिली भक्ति से हो रहे हैं अवैध प्लान स्वीकृत

ग्रीन बेल्ट में अवैध कॉलोनीया स्वीकृत हो रही है लोगों के साथ भूमाफिया कर रहे हैं धोखाधड़ी

स्थानिय प्रशासन की मिली भक्ति के बिना अवैध कार्य नहीं सकते हैं भूमाफिया व अधिकारी धन लुट रहे हैं

द पुलिस पोस्ट

शिवगंज नगर पालिका क्षेत्र व पैराफैरी क्षेत्र के मास्टर प्लान के रिंग रोड पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना व कॉलोनी काटी जा रही है पालिका प्रशासन व वरिष्ठ नगर नियोजक जोधपुर व स्वायत्त शासन विभाग जयपुर के अधिकारियों की मिली भक्ति कहां या लापरवाही सिर्फ धन के बल पर प्लान स्वीकृत किया है व यहाँ पर कॉलोनी के नाम पर एक गोरख धंधा चालू है लोगों को गुमराह कर प्लॉट बेच जाते हैं लोगों से धोखा हो जाता है पालिका में जो प्लान स्वीकृत होता है उसका मुख्य सड़क 40 फीट होता है पर कॉलोनी मालिक मुख्य सड़क को 20 फीट या 30 फीट सड़क की छोड़ते हैं जो लोगों के साथ धोखाधड़ी है अगर प्रार्थी पट्टे बनाना चाहे तो उसके अपने जमीन में से सड़क की भूमि देनी पड़ती है इससे वह सड़क मुख्य 40 फुट होता है और पालिका कृषि भूमि और काटने वाले कॉलोनी वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते इसलिए यह भू माफिया कृषि के नाम पर प्लॉट काटकर बेचकर चले जाते हैं इस क्षेत्र की जनता रोती है क्योंकि वह तो अपना पैसा वसूल कर चले जाते हैं फिर कॉलोनी में सुविधा नाम की कोई चीज नहीं मिलती ओपन लैंड सुविधा क्षेत्र फैसिलिटी मोबाइल टॉवर विधुत पॉइंट सही स्कूल सुविधा नहीं मिलती अगर वह अपने पैसों से विकास कब होगा तो विकास होगा नहीं तो नाली सड़क लाइट पानी सब से वंचित रहेंगे मास्टर प्लान में जिस जगह सड़क है कुछ लोग को भी यह भूमाफिया इधर-उधर कर देता है रिंग रोड 100 फीट उसके बीच में लोग अपनी कॉलोनीया मुख्यमंत्री जन आवास योजना कॉलोनी काट रहे हैं जब यह रिंग रोड चालू होगा सब लोग सोचेंगे कि अपनी जमीन कहां गई जिन लोगों को रोना पड़ेगा अगर प्रशासन अब भी सूचित कर इन सभी चीजों की जांच कर लेवे और अपने कनिष्ठ अभियंता तकनीकी अधिकारी है उनसे जांच कराओ या वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा फजीर्वांडा कर जाँच करवा कर भेज रहे प्लानो को वापस जांच करवाए जाए या नक्शा प्लान स्वीकृत कर लाकर जांच करें तो मालूम पड़ जाएगा की वास्तविक जमीन कहां पर है और मालिक कहां पर बनकर बैठा है इन सभी की जांच होनी चाहिए तब जाकर सड़कों पर काटा प्लानो को जनता के साथ उन्हें हुए धोखे से बचाया जा सके शहर से कांवेन्शन जी मंदिर जाने वाले रोड पर एक मुख्यमंत्री जन



आवास योजना का कार्य चालू है उस योजना के आगे करीब 160200 फीट सरकारी बिलानाम भूमि है उस भूमि पर भी उस प्रार्थी ने कब्जा कर दिया है फिर यह लोग अपनी जमीन को भी मास्टर प्लान के चक्कर में इधर-उधर कर देते हैं जिससे यह अपनी जमीन बचा सके इस जमीन के आगे वह बीच में होकर 100 फीट रिंग रोड सड़क निकल रही है और चौराहा है जिसका 15 मीटर चारों तरफ सर्कल का रेडिएशन होता है इस भूमि को भी अपनी तरफ कर देते हैं फिर भविष्य में यह रिंग रोड और चौराहे बनेगा तब यह कॉलोनी बीच में आएगी सब जमीन इधर से उधर काटनी पड़ जाए तो फिर यहां पर खरीदने वालों को ही नुकसान होगा अब सत्यता की जांच कर इस कॉलोनी के आगे पीछे अंदर होकर जो निकल रही सड़क की जांच और सर्कल की जांच कर लेवे तो दूध का दूध और पानी का पानी निकल जाएगा ऐसे ही शिवगंज शहर में वह फेरा फेरी क्षेत्र में कई जगह पर यह गोरखधंधा हो रहा है जिसमें मास्टर प्लान के सड़कों के साथ हेरा फेरी किए मास्टर प्लान सड़कों पर आज भी वाणिज्य बिल्डिंग काम चालू है और सरकारी जमीन पर भी कब्जे कर रहे हैं क्या करें यहाँ पर विराजे नगर पालिका अध्यक्ष और कई नेताओं की मिली भक्ति से अवैध कार्य चालू है यहाँ मुख्य कॉलेज से लेकर रीको इंडस्ट्रीज एरिया की तरफ जाने वाली सड़क पर सरकारी जमीन पर

भी दुकाने लोगों ने बना दी उनको रोकने वाला कोई नहीं है क्योंकि प्रशासन को उन्होंने धन से खरीद लिया इसलिए प्रशासन कोई नहीं है फिर यह लोग दादागिरी करते हैं वह जान से मारने की धमकी देते हैं शिवगंज की जनता बहुत ही अच्छी वह सीधी है यह लोग बाहर से आकर सरकारी जमीन पर कब्जा करना और मास्टर प्लान रिंग रोड पर अपनी दुकानें बनाना फिर जनता को बेचकर धन लेकर चले जाएंगे फिर यहाँ सीधी जनता को भुगतना पड़ेगा क्योंकि पालिका प्रशासन पहले ही इनके विरुद्ध कार्रवाई कर काम रुकवा दे यहां बिल्डिंग को सीज कर दे या बिल्डिंग को हटा दें तो उस जनता के साथ धोखा नहीं होता जो इस बिल्डिंग को खरीदते हैं सरकारी जमीन पर दुकानें खुलेआम बन जाएंगी पालिका प्रशासन कुछ नहीं कर सकती तो इसका मतलब यह सब मिले हुए हैं इस पर बड़े लोगों का हाथ है शिवगंज नगर पालिका में यह गोरखधंधा प्रशासन शहरों के संग अभियान चलने के बाद ही यह अवैध कार्य चालू हुए हैं और पालिका में भूमि शाखा में विराजे बाबूजी इन लोगों को सलाह देते हैं और अवैध कार्य करवाते हैं नगर पालिका इनको नियम अनुसार नहीं करेगा और कॉलेज से आगे सड़क के दोनों तरफ करीब 40 यहाँ 45 फीट का सरकारी बिलानाम भूमि

है फिर भी यह लोग उस सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और दुकाने और मकान बना रहा है इनको कोई रोकने वाला नहीं है इसलिए सब यह अवैध कार्य हो रहा है पालिका प्रशासन में विराजे सफाई निरीक्षक साहब सिर्फ आफिस में ऐसी रूम में बैठे रहते हैं इन्होंने अपने चार पाँच आदमी अपने पास रखे हुए हैं जो शहर में जगह जगह पर जाकर धन इकट्ठा कर लाकर ईन एस आई साहब तक पहुँच जाता है गलत कार्य चलता रहता है कोई ध्यान नहीं देने वाला कोई नहीं है इसलिए शहर में बिल्डिंग लाईन से बहार निर्माण व अतिक्रमण हो रहे हैं मास्टर प्लान के विपरीत निर्माण हो रहे हैं इनका क्या कहना है शिवगंज नगर पालिका क्षेत्र में मास्टर प्लान के विपरीत बड़ी बड़ी

आवासीय योजना व कॉलोनी काटी जा रही है बिना प्लान स्वीकृत नक्शा पास किए बिना पट्टा जारी हो रहे है पालिका प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है हमे उच्च न्यायालय का सहारा लेना पड़ेगा शिवगंज से केसरपुरा व कामवेश्वरजी महादेव मंदिर जाने वाले सड़क पर एक मुख्यमंत्री जन आवास योजना व अन्य कॉलोनी काटी गई है जो नियमों के विपरीत अवैध रिसोर्ट का निर्माण हो रहा है कार्रवाई कोई नहीं करता है जब रिंग रोड का निर्माण होगा तब कहीं जाएंगे यह अधिकारी व भूमाफियाओं की सातगाँठ से अवैध कार्य व अतिक्रमण हो रहे है सीमा देवी माली पाषंद नगर पालिका शिवगंज शिवगंज नगर पालिका क्षेत्र में मास्टर प्लान के विपरीत निर्माण हो रहे हैं

बिना प्लान स्वीकृत नक्शा पास किए बिना पट्टा जारी हो रहे है रिंग रोड पर अतिक्रमण चल रहा है बड़े अधिकारियों की मिली भक्ति से अवैध कार्य हो रहे है सरकारी जमीन पर कब्जा करवा रहे है पालिका प्रशासन जिससे शिवगंज शहर की जनता के साथ धोखाधड़ी कर रहे है पालिका प्रशासन ने जितने भी पट्टे जारी किए गए है उनकी जाँच करवा कर तुरंत ही खारिज करावे पालिका प्रशासन के राजस्व के नुकसान पहुँचाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए कमलसिंह चौहान समाजसेवी गौरक्षक एव उधमी शिवगंज शिवगंज खेजडिया रोड पर कई कॉलोनी अवैध बन रही है जो पैरा फेरी में ग्रीन बेल्ट में प्लॉट काटे जा रहे हैं

भूमाफिया सक्रिय है क्योंकि उन्होंने अपने दलाल छोड़ रखे हैं जो पालिका के अधिकारी को सेटिंग करके रखते हैं पालिका प्रशासन का राजस्व नुकसान करते हैं सिर्फ अपना राजस्व बढ़ाते है इसके अलावा कुछ काम नहीं करते हैं पालिका का करोड़ों का नुकसान कर अपना फायदा उठाना इस सड़क पर जितनी भी कॉलोनी स्वीकृत हुई है इतनी सभी की जांच करवा कर तुरंत ही उनके पट्टे खारिज होने चाहिए जो मास्टर प्लान नियमों की विपरीत पट्टे बने हैं उन सभी की जांच होनी चाहिए व रिंग रोड का निर्माण होना चाहिए व अवैध अतिक्रमण को हटाना चाहिए जैसाराम माली अध्यक्ष जवाई पर्यावरण एवं वन विकास समिति शिवगंज

गोकुल मित्र मंडल की कार्यकारणी के चुनाव सम्पन्न माली अध्यक्ष बने

सैकड़ों लोगो ने सभी मंडल पदाधिकारीओ का माला पहनाकर स्वागत-सत्कार किया

द पुलिस पोस्ट

शिवगंज आज को श्री गोकुल मित्र मंडल शिवगंज की अतीत आवश्यक बैठक शहर के केरलेशवर महादेव मंदिर में रखी गई जिसमें श्री गोकुल मित्र मंडल के नवीन कार्यकारणी घोषित की गई जिसमें सर्वसम्मति से गोविंद माली को अध्यक्ष, माली अर्जुन गहलोत को उपाध्यक्ष, मनीष सोनी को कोषाध्यक्ष, सतीश चौहान को मंत्री, राणु गोस्वामी को संयोजक व सदस्य के रूप में अशोक चौहान, मुकेश कुमावत, दिलीप भारती, दिलीप सोनी, नकुल त्रिवेदी, दुष्यंत वैष्णव, संजय सुथार



, किशोर कोलीवाडा, रतन सुथार, महेंद्र सुथार, सुरेश प्रजापत, राजू भाई, मयूर दत्ता को मंडल का सदस्य बनाया गया बैठक में आगामी कार्यक्रम कृष्ण जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम के साथ मनाने का निर्णय लिया जिसमें 25 अगस्त को दोपहर महिला भजन संध्या, 26 अगस्त को रात्रि विशाल भजन संध्या, 27 अगस्त को भव्य शोभा यात्रा व क्रेन वाली मटकी फोड़ कार्यक्रम मनाने का निर्णय लिया??

7 वर्ष पुराने रिश्वत प्रकरण में अलवर एसीबी की कार्रवाई देवस्थान विभाग के एडिशनल कमिश्नर (आरएएस) आकाश रंजन को जयपुर से किया गिरफ्तार

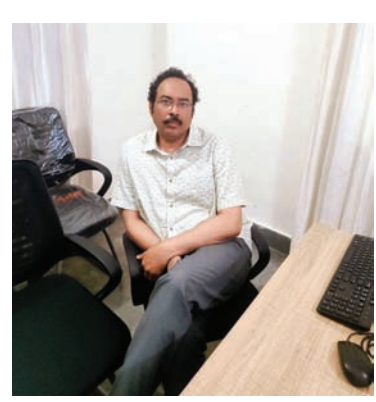
एसीबी अलवर पुलिस उप अधीक्षक महेंद्र मीणा की टीम ने किया गिरफ्तार

द पुलिस पोस्ट

आकाश रंजन ने तिजारा तहसीलदार रहते हुए वसीयतनामा में निर्णय कराने के नाम पर माँगी थी 8 हजार रुपए की रिश्वत एंकर--अलवर एसीबी की टीम ने देवस्थान विभाग के एडिशनल कमिश्नर (आरएएस) आकाश रंजन को रिश्वत मांगने के मामले में गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम ने कोर्ट से जारी गिरफ्तारी वारंट की पालना करते हुए आकाश रंजन

को जयपुर के मेरी गोलड पब्लिक स्कूल एसटीसी/बीएड कॉलेज बड़ पीपली (सीकर रोड) से गिरफ्तार किया है। आकाश रंजन को आज कोर्ट में पेश किया गया। एसीबी से मिली जानकारी के अनुसार साल 2017 में हुए रिश्वत के मामले में आरोप प्रमाणित होने पर यह कार्रवाई की गई है। उस दौरान आकाश रंजन तहसीलदार के पद पर तैनात थे। तिजारा के रहने वाले परिवारी चंद्र सिंह ने एसीबी चौकी अलवर में 19 जुलाई 2017 को एक रिपोर्ट दी थी। जिसमें एसीबी अलवर ने 20 जुलाई 2017 को कार्रवाई करते हुए दलाल मानसिंह

और सहायक कार्यालय अधीक्षक राधेश्याम मौर्य तहसील तिजारा को गिरफ्तार किया था। तहसीलदार रंजन का रिश्वत मांगने और प्राप्त करने में सम्मिलित होना पाया गया था। लेकिन आकाश रंजन मौके से फरार हो गया था। उनके खिलाफ एसीबी कोर्ट अलवर में 16 फरवरी 2022 आकाश रंजन ने तिजारा तहसीलदार रहते हुए वसीयतनामा में निर्णय कराने के नाम पर माँगी थी 8 हजार रुपए की रिश्वत चार्जशीट पेश की गई थी। आरोपी आकाश रंजन नोटिस के बाद भी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। आकाश रंजन अभी सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग जयपुर में तैनात



हैं। इस पर कोर्ट ने आरोपी आकाश रंजन का गिरफ्तारी वारंट जारी किया। इस पर एसीबी द्वारा गिरफ्तारी की गई।

जिला पार्षदों का आरोप -लोकतंत्र की हो रही हत्या,अविश्वास प्रस्ताव के बाद भी नहीं मिल रही फ्लोर टेस्ट की तारीख

द पुलिस पोस्ट



हनुमानगढ़ जिले के भादरा में पिछले सप्ताह नगर पालिका के अध्यक्ष पद के 8 जुलाई को होने वाले चुनाव में वोटिंग के समय ऐन वक्त पर चुनाव रद्द करने से विवाद हो गया था। पूर्व विधायक बलवान पुनिया ने राज्य की भाजपा सरकार व भाजपा नेताओं द्वारा प्रशासन पर दबाव बनाकर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया है। सुबह दस बजे करीब 21 पार्षद मतदान के लिए नगरपालिका पहुंचे और सवा घंटे इंतजार के बाद उन्हें सहायक निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अचानक निर्वाचन अधिकारी मेडिकल अवकाश पर चले गए। ठीक ऐसी ही घटना इस समय अलवर में भी चल रही है जहां करीब 15 दिन पहले जिला परिषद अलवर के जिला परिषद सदस्यों ने जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर के खिलाफ मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतिभा वर्मा को अविश्वास प्रस्ताव का पत्र दिया लेकिन उस समय मुख्य

कार्यकारी अधिकारी ने उन्हें शासन सचिव रवि जैन के पास आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया। जब जिला पार्षद जयपुर शासन सचिव के पास पहुंचे तो शासन सचिव ने उन्हें संभागीय उसके पास जाने को कहा और संभागीय आयुक्त ने इसके बाद उन्हें जिला कलेक्टर के पास जाने के लिए कहा। जिला परिषद के सदस्य अलवर जाकर जिला कलेक्टर से मिले और उन्हें अविश्वास प्रस्ताव जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता को दिया। इसके कई

दिन बाद तक अलवर जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने जब फ्लोर टेस्ट की तारीख नहीं दी तो जिला पार्षद देर रात उनके कार्यालय और निवास पर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने कहा कि सारी कार्रवाई मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतिभा वर्मा की ओर से की जाएगी। फिर पिछले सप्ताह जिला परिषद के सदस्य सीईओ से मिले तो सीईओ ने कहा कि पूर्व में दिए गए अविश्वास प्रस्ताव के स्थान पर आज की तारीख में नया अविश्वास प्रस्ताव लिखकर देने पर

तारीख दी जाएगी। तब वहां मौजूद सभी जिला पार्षदों ने फिर से नया अविश्वास प्रस्ताव मुख्य कार्यकारी अधिकारी को दिया लेकिन अभी तक अविश्वास प्रस्ताव के लिए फ्लोर टेस्ट की तारीख नहीं मिली है। जिला पार्षदों ने एक स्वर में कहा कि 17 जिला पार्षद अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए पर्याप्त थे लेकिन फिर भी उनकी ओर से 19 सदस्यों की मौजूदगी वाला हस्ताक्षर युक्त अविश्वास प्रस्ताव मुख्य कार्यकारी अधिकारी को दिया है लेकिन अधिकारी पिछले 15 दिन से जिला परिषद के सदस्यों को राजनीतिक दबाव में इधर से उधर तो भेज रहे हैं लेकिन फ्लोर टेस्ट की तारीख नहीं दे रहे। इस बीच में सब कुछ मैनेज किया जा रहा है। एक जिला पार्षद ने बताया कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लोकतंत्र में प्रावधान है कि चुने हुए जनप्रतिनिधि को 2 साल के बाद अविश्वास प्रस्ताव लाकर हटाया जा सकता है लेकिन अब चुने हुए दो दर्जन जनप्रतिनिधियों की ओर

से ले जा रहे अविश्वास प्रस्ताव के अनदेखी अफसर कर रहे हैं जिसकी शिकायत उच्च स्तर पर की जाएगी। हाल ही में यह मामला विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने उठाया था। जिला पार्षद संदीप फौलादपुरिया का कहना है कि बार-बार अफसर नियमों का परीक्षण करने की बात कह कर फ्लोर टेस्ट की तारीख नहीं दे रहे इससे मिली भगत उजागर होती है। सरकार के दबाव में ऐसा किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के टिकट पर जिला प्रमुख बने बलबीर सिंह छिल्लर के व्यवहार से खफा होकर जिला परिषद सदस्यों ने करीब 15 दिन पहले अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। बलबीर सिंह छिल्लर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा में शामिल हो गए। जिला परिषद अलवर में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या ज्यादा है। बलबीर सिंह छिल्लर बीजेपी के ही रामवीर शाहबादी को हराकर जिला प्रमुख बने थे।

रक्तदान शिविर में एकत्र हुआ 121 यूनिट रक्त

द पुलिस पोस्ट



बिजयनगर ब्यावर। मधु मैसी परिवार द्वारा स्वर्गीय एसपी मैसी की तीसरी पुण्यतिथी पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर की शुरुआत सुबह नौ बजे दीप प्रज्वलन के साथ की गई। भीलवाड़ा ब्लड बैंक के सहयोग में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर होटल एन चंद्रा में आयोजित किया गया। रक्तदान शिविर के समापन तक कुल 121 यूनिट रक्त एकत्र किया गया। उक्त शिविर में भाजपा नेता आशीष सांडू केलाश गुर्जर सहित श्रीमती दीपिका वर्मा ने शिरकत की। सिस्टर मधु मैसी व उनके परिवार द्वारा सभी रक्तवीरों का प्रशस्ति पत्र व उपहार भेंट कर आभार व्यक्त किया। मधु मैसी परिवार व सर्व मसीह समाज ने उक्त शिविर में बढ चढ़कर भाग लिया। रक्तदान शिविर को सफल बनाने में श्री मति मधु मैसी सिस्टर, अनुग्रह जॉन, सुनिधि मैसी,साक्षी मैसी बॉबी विसंट ओर,विशाल इनोसंट अनुग्रह अभिषेक रोजलीन मार्शल मोरविन सिंह दीपक सेन कमलेश लोहार व समस्त गार्गी हॉस्पिटल भीलवाड़ा स्टाफ ने सहयोग प्रदान किया।

सिख समाज ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन



द पुलिस पोस्ट

बिजयनगर ब्यावर। ट्रस्ट श्री गुरु सिंह सभा कमेटी बिजयनगर जिला ब्यावर की तरफ से सोमवार कोजतहसीलदार शिल्पा चौधरी के मार्फत मुख्यमंत्री जयपुर को ज्ञापन भेजा गया। जिसमें बताया गया है कि भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है देश के संविधान में सभी धर्मों को समान रूप से अधिकार दिये गये हैं व बिना भेदभाव के प्रत्येक नागरिक को वाक एवं अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता प्रदान की गई है। किन्तु वर्तमान में संविधान की रक्षा करने वालों को चुप कराने के लिए व आवाज को दबाने के लिए स.तेजेन्द्रपालसिंह टिम्मा मुख्य सेवादार गुरुद्वारा बाबा दीपसिंह शहीद श्री गंगानगर व अध्यक्ष धर्मप्रचारक एसजीपीसी राजस्थान पर देशद्रोह जैसे गंभीर प्रकृति के झूठा मुकदमा पुलिस थाना श्री गंगानगर में दर्ज करवाया गया है जो की निन्दनीय है जिसका पूरे बिजयनगर व गुलाबपुरा की संगत के द्वारा रोष व्यक्त किया। ज्ञापन देने में ट्रस्ट श्री गुरु सिंह सभा के प्रधान हरगोविंद सिंह टुटेजा, सचिव दिलप्रीत सिंह टुटेजा, कोषाध्यक्ष जगजीत सिंह टुटेजा, नवनीत सिंह टुटेजा, हरमीत सिंह टुटेजा, गगन दीप सिंह राजन सिंह टुटेजा, सदस्य आदि थे।

महिला की हत्या का आरोपी गिरफ्तार

द पुलिस पोस्ट

खेतड़ी। महिला को गाड़ी से कुचलकर हत्या के मामले में खेतड़ी पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बदमाश तीन से साल से फरार चल रहा था। आरोपी को जिले के टॉप टेन बदमाशों में शामिल कर तीन हजार रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। सीआई भंवरलाल कुमावत ने बताया कि फिरासावाली ढाणी तन कांकरिया निवासी सुरेश सैनी ने 11 जून 2021 को रिपोर्ट दी कि सुबह करीब पांच बजे उनके घर पर एक कैपूर व थार गाड़ी में करीब दस लोग सवार होकर आए। इस दौरान बलराम ने पिस्टल से दो राउंड फायर कर दहशत फैलाई तथा उसके परिवार के लोगों को गाड़ी में डालकर ले गए। इस दौरान आरोपियों ने उसकी माता सोनी देवी को गाड़ी से पटक कर बेरहमी से मारपीट की तथा गाड़ी से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद आरोपियों ने उसके पिता, भाई के साथ भी सरियों से बेरहमी से मारपीट की। जब गांव के अन्य लोग आए तो आरोपी उन्हें घायलवास्था में छोड़कर फरार हो गए। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी प्रवीण कुमार ने विशेष टीम का गठन कर मामले में फरार चल रहे आरोपियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए, जिस पर पुलिस की टीम लगातार आरोपियों के संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि महिला की हत्या के मामले में फरार आरोपी खेतड़ी कस्बे में आया हुआ है। जिस पर पुलिस की टीम ने दबिश देकर ढाणी भोपाला तन कांकरिया निवासी हरिराम गुर्जर पुत्र गणपत राम को गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी से गहनता से पूछताछ की जा रही है तथा वादावत में शामिल अन्य आरोपियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।

पुश्तैनी मकान पर कब्जे के शक में बहन की हत्या:मां और छोटे भाई के साथ रहती थी;2 बार तलाक हो चुका था

द पुलिस पोस्ट

जोधपुर। बहन के 2 तलाक हो गए थे। वह पीहर में आकर रह रही थी। किराना के थोक व्यापारी बड़े भाई को शक था कि वह यहां रहकर पुश्तैनी मकान पर कब्जा करना चाहती है। उसे यह भी लगता था कि जिन लोगों को उसने 30 लाख रुपए उधार दे रखे हैं, बहन उन्हें भी भड़का रही है। ऐसे में वह धारदार चाकू लेकर पुश्तैनी मकान पहुंचा और झगड़े के बाद गले पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर बहन की हत्या कर दी। इसके बाद थाने जाकर सरेंडर कर दिया। मामला जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड का रविवार रात 8:15 बजे का है। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के थाना इंचार्ज नितिन दवे ने बताया- चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के सेक्टर-21 में रहने वाली गुडु?डी उर्फ चंद्रा सिंधी (47) पुत्री मोहनलाल की हत्या के मामले में बड़े भाई पुरुषोत्तम सिंधी (48) को गिरफ्तार किया गया है। वह खुद थाने पहुंचा था और सरेंडर कर दिया था। छोटे भाई जमनादास (40) की पत्नी हेमा ने मामला दर्ज करवाया है। मामले में जांच जारी है।

तलाक के बाद छोटे भाई और मां के साथ रहती थी

पुलिस के अनुसार, गुडु मां, छोटे भाई



जमनादास और भाभी हेमा के साथ पुश्तैनी मकान में रहती थी। जांच में सामने आया कि गुडु?डी की दो बार शादी हुई थी। लेकिन, दोनों बार ही तलाक हो गया और वह मां व भाई के साथ पुश्तैनी मकान में रहने आ गई थी। आरोपी बड़ा भाई पुरुषोत्तम शहर के चौहाबे इलाके के

सेक्टर-9 में परिवार के साथ अलग मकान में रह रहा था। रविवार शाम 7:15 बजे पुरुषोत्तम सेक्टर-21 वाले मकान पर आया। वह मां और बहन गुडु से मिला। जांच में सामने आया कि यहां गुडु?डी के साथ पैसें और प्रॉपर्टी को लेकर उसका विवाद हो गया। आवेश में आकर पुरुषोत्तम

ने चाकू से बहन की गर्दन और शरीर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। गुडु?डी ने बचाव किया तो पुरुषोत्तम का हाथ भी चाकू से जखमी हो गया। गुडु?डी लहलुहान होकर फर्श पर गिर पड़ी। घर में चीख-पुकार मच गई। गुडु?डी को मरा समझकर पुरुषोत्तम घर से निकल गया। खून सने हाथ और

कपड़े पहने वह सीधे चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाने पहुंचा और सरेंडर कर दिया। उसने पुलिस को बताया कि वह बहन का मर्डर करके आ रहा है। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। इसके बाद एडीसीपी (पश्चिम) निशांत भारद्वाज, चौहाबे थानाधिकारी नितिन दवे और एसआई फगलूराम टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जहां लहलुहान हालत में गुडु?डी फर्श पर पड़ी मिली। उसे फौरन एमडीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान गुडु?डी की मौत हो गई।

बहन के घर में रहने पर थी आपत्ति

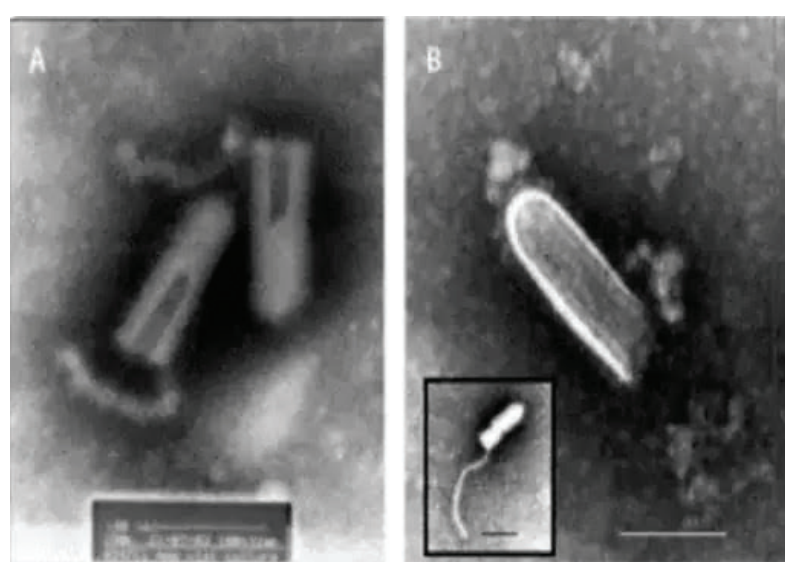
प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि पुरुषोत्तम चौपासनी स्थित पुश्तैनी मकान को अपना बताता था। तलाक के बाद गुडु?डी मां और छोटे भाई के साथ इस मकान में रह रही थी। इससे पुरुषोत्तम को आपत्ति थी। उसे लगता था कि गुडु उसके मकान पर कब्जा करना चाहती है। पूछताछ में यह भी सामने आया है कि पुरुषोत्तम ने बिजनेस के लिए कुछ व्यापारियों को 30 लाख रुपए भी दे रखे थे। जब पुरुषोत्तम उनसे रकम लौटाने की मांग करता तो गुडु उन लोगों को भड़का कर रुपए नहीं लौटाने की बात कहती थी।

राजस्थान में आया बच्चों से जुड़ा खतरनाक वायरस, एक मौत: उदयपुर के 2 मासूमों में मिले चांदीपुरा संक्रमण के लक्षण

उदयपुर। राजस्थान में चांदीपुरा वायरस की एंटी हो गई है। उदयपुर के दो बच्चों में वायरस के लक्षण मिले थे। दोनों का इलाज गुजरात में चल रहा था। तीन साल के एक बच्चे की 27 जून को मौत हो गई, जबकि दूसरे का इलाज जारी है। वह खतरे से बाहर है। उधर, उल्टी-दस्त से पीड़ित बच्चों की निगरानी शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग घर-घर सर्वे करा रहा है। उदयपुर के डिप्टी सीएमएचओ अंकित जैन ने बताया- राज्य सरकार से रविवार को सूचना मिली थी कि उदयपुर जिले के खेरवाड़ा और नयागांव के दो बच्चों में चांदीपुरा वायरस के लक्षण मिले हैं। दोनों को गुजरात के हिम्मतनगर स्थित सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बच्चों के ब्लड और सीरम के सैंपल पुणे भिजवाए गए। इसकी रिपोर्ट आनी बाकी है।

इलाज के दौरान एक की मौत

डिप्टी सीएमएचओ अंकित जैन ने बताया- खेरवाड़ा के बलीवा गांव में बच्चा 26 जून को अपने घर पर था। अचानक उसे दौरे आने लगे। पहले उसे भीलूड़ा (उदयपुर) सीएमएचओ ले गए। वहां से हिम्मतनगर (गुजरात) सिविल हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। दूसरे दिन उसकी मौत हो गई। दूसरा केस खेरवाड़ा के ही बावलवाड़ा गांव की बच्ची (5) का है। बच्ची को 5 जुलाई को उल्टी-दस्त, बुखार की शिकायत के बाद



पहले ईडर (गुजरात) हॉस्पिटल ले जाया गया था। बाद में उसे हिम्मतनगर (गुजरात) रेफर किया गया। उसका आईसीयू में इलाज चल रहा था। दो दिन पहले उसे बार्ड में शिफ्ट किया गया। बच्ची अब स्वस्थ है।

दोनों इलाकों में शुरू किया सर्वे सीएमएचओ डॉ. शंकर बामनिया ने बताया- दोनों इलाकों खेरवाड़ा और नयागांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सोमवार को सर्वे कराया है। दोनों जगह 35 घरों के सर्वे में अभी ऐसा कोई मरीज नहीं मिला है, जिसमें चांदीपुरा संक्रमण के लक्षण हों। बीमार बच्चे

वर्ष 1966 में महाराष्ट्र के चांदीपुरा में हुई थी इस वायरस की पहचान

वर्ष 1966 में महाराष्ट्र के नागपुर स्थित चांदीपुरा गांव में चांदीपुरा वायरस की पहचान हुई थी। इसके बाद इस वायरस को वर्ष 2004-06 और 2019 में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में रिपोर्ट किया गया था। चांदीपुरा वायरस एक फ्लू आ वायरस है। यह वायरस सबसे अधिक मादा फ्लेबोतोमाइन मक्खी से ही फैलता है। मच्छर में एडीज ही इसके पीछे ज्यादातर जिम्मेदार है। 15 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा इसका शिकार होते हैं। उन्हीं में मृत्यु दर भी सबसे ज्यादा रहती है। चांदीपुरा के इलाज के लिए आज तक कोई एंटी वायरल दवा नहीं बनी है। इस मैकेनिज्म में यदि दवा या वैक्सिन ईजाद की जाए तो चांदीपुरा वायरस फैलाने वाले रोग स्रोसंज पर कंट्रोल रखा जा सकता है।

मस्तिष्क में सूजन आ जाती है, मौत तक हो जाती है

चांदीपुरा वायरस के संक्रमण के दौरान शरीर के माइक्रोग्लियल सेल्स में माइक्रो आरएनए -21 की संख्या बढ़ने लगती है। इससे कोशिकाओं में फोस्फेटेस और टेनसिन होमोलोग (ढब्ल्यूएच) पदार्थ का सिक्रिशन कम हो जाता है। इससे इसानों की माइक्रोग्लियल कोशिकाओं में न्यूक्लियर फैक्टर कापा लाइट-चैन-एनहांसर ऑफ एक्टिवेटेड बी सेल्स या साइटोकाइन्स की सक्रियता बढ़ जाती है। इससे मस्तिष्क में सूजन हो जाती है। इससे तेज बुखार, उल्टी, ऐंठन और कई मानसिक बीमारियां आ जाती हैं। इसके कारण मरीजों में इंसेफेलाइटिस के लक्षण भी दिखने लगते हैं और मरीज कोमा में चला जाता है। कई बार तो मौत तक हो जाती है। इन लक्षणों को एक्वूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम (आरए) की कैटेगरी में रखा गया है।

एक्टिविटी जारी है। बीमार बच्चों में निर्देश जारी करते हुए बुखार और आसपास घर-घर सर्वे कराया जा रहा है। उल्टी-दस्त से पीड़ित बच्चों पर विशेष सभी सीएचओ और एएनएम को इस संबंध में निर्देश जारी करे हुए बुखार और उल्टी-दस्त से पीड़ित बच्चों पर विशेष ध्यान देने को कहा है।

टैंक में डूबने से दो मासूम बहनों की मौत स्टोन फैक्ट्री में खेलते समय 5 फीट गहरे टैंक में गिरी, आधे घंटे बाद पता लगा

कोटा। शहर के अंतपुरा थाना क्षेत्र में स्टोन फैक्ट्री के टैंक में डूबने से दो मासूम बालिकाओं की मौत हो गई। दोनों सगी बहनें थीं और अपने माता पिता के साथ फैक्ट्री पर रहती थीं। बताया जा रहा है कि खेलते समय दोनों पानी के टैंक में चली गईं। करीब घंटे तक दोनों के नहीं मिलने पर परिजनों ने तलाश शुरू की।



पिता दूढ़ता हुआ टैंक के पास पहुंचा तो घटना का पता लगा। दोनों को बाहर निकालकर इलाज के लिए हॉस्पिटल लेकर आए। जहां इयुटी डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित किया। परिजनों ने कार्रवाई नहीं चाहने की कहकर पोस्टमॉर्टम करवाने से इनकार कर दिया। जिसके बाद पुलिस ने बिना पोस्टमॉर्टम के शव परिजनों को सौंप दिया।

अंतपुरा थाना ASI कुंदन सिंह ने बताया- बच्चियों के पिता डुबेल एम्पी के कांकरा का रहने वाला हैं। डेढ़ साल पहले मजदूरी के लिए कोटा आया था। पत्नी व बच्चियों के साथ इंदरप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र रोड नंबर 5 स्थित बालाजी स्टोन फैक्ट्री में रह रहा था। फैक्ट्री मालिक ने रहने के लिए उसे एक

कमरा दे रखा था। डुबेल आज मजदूरी के लिए गया हुआ था। दोपहर साढ़े 4 बजे करीब उसकी बेटियां काली (3 साल) व खीना (4 साल) फैक्ट्री में खेल रही थीं। पत्नी कमरों में थी। खेलते समय दोनों बच्चियां फैक्ट्री के पीछे वाले हिस्से में चली गईं। पीछे टैंक बना हुआ है। जिसमें स्टोल कटिंग का पानी गिरता है। टैंक में 5 फीट के करीब पानी भरा था। दोनों

बच्चियां टैंक में डूब गईं। शाम 5 बजे करीब पिता डुबेल मजदूरी करके लौटा। बच्चियों के नहीं दिखने पर उसने पत्नी से पूछा। पत्नी ने बताया कि बाहर खेल रही होगी। जिसके बाद डुबेल बच्चियों को ढूँढता हुआ फैक्ट्री के पीछे वाले हिस्से में पहुंचा। तब घटना का पता लगा। परिजनों स्टोल कटिंग का पानी गिरता है। टैंक में 5 फीट के करीब पानी भरा था। दोनों

बड़ी सादड़ी में टी.बी. मुक्त भारत अभियान स्कूल कार्यक्रम, नुककड नाटक, नारा लेखन, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता से किया जाएगा जागरूक

बड़ी सादड़ी। वर्ष 2025 तक टीबी रोग की समाप्ति के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए खण्ड बड़ीसादड़ी में टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत टारगेट जनसंख्या का आशा सहयोगिनीयों, एएनएम, सीएचओ द्वारा घर-घर जाकर सर्वे किया जाएगा। खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. विश्वास खोईवाल ने बताया कि दो



सप्ताह से ज्यादा खांसी, शाम के समय बुखार, खांसी के साथ खून आना, छाती में दर्द व सांस फूलना, गर्दन या बगल में दूढ़ता हुआ फैक्ट्री के पीछे वाले हिस्से में पहुंचा। तब घटना का पता लगा। परिजनों स्टोल कटिंग का पानी गिरता है। टैंक में 5 फीट के करीब पानी भरा था। दोनों

उच्च तकनीकी वाली सीबीनाट मशीन भी उपलब्ध है, ताकि मरीजों को अन्य सस्थानों पर भटकना ना पड़े। हर टीबी मुक्त ग्राम पंचायत में टीबी की जन जागरूकता के लिए स्कूल कार्यक्रम, नुककड नाटक, नारा लेखन, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी।

पुनावली गांव में 200 बीघा चारागाह भूमि पर पौधारोपण 25 हजार पौधे लगाए जाएंगे, पूरे बड़ी सादड़ी में 1 लाख 11 हजार पौधे लगाने का लक्ष्य



बड़ी सादड़ी। बड़ी सादड़ी के पुनावली गांव में 200 बीघा चारागाह भूमि पर पौधारोपण अभियान की शुरुआत की गई। इस चारागाह में 25 हजार पौधे लगाए जाएंगे। एसडीएम कल्पित शिवरान के नेतृत्व में इस अभियान की शुरुआत की गई। पौधारोपण के ब्लॉक प्रभारी भगवत सिंह शकवत ने हरित एप के बारे में जानकारी दी। उन्होंने सभी को पौधे लगाने और उनकी परवरिश करने का संकल्प दिलाया। एसडीएम कल्पित शिवरान ने हरित एप डाउनलोड कर पौधा रोपण कर उसके साथ फोटो और सेल्फी खींच कर जिला प्रशासन से प्रमाण पत्र लेने की अपील की। पुनावली स्कूल के सभी छात्र छात्राओं ने भी पौधारोपण किया। इस अवसर पर ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी ने शिक्षा विभाग ब्लॉक बड़ी सादड़ी में लगभग 65 हजार पौधे लगाने का लक्ष्य लिया है। विकास अधिकारी लक्ष्मण लाल

मीणा ने कहा कि पंचायत राज विभाग की ओर से 28 हजार पौधे लगाने की जानकारी देते हुए कहा कि पेड़ों को बचाना ही हमारा धर्म है। इस चारागाह भूमि पर 25 हजार लगाए जाएंगे। बड़ी सादड़ी उपखण्ड क्षेत्र में एक लाख ग्यारह हजार एक सौ पौधे इस मानसूनी सीजन में लगाने का लक्ष्य एसडीएम कल्पित शिवरान के नेतृत्व में रखा है। इस अवसर पर विकास अधिकारी लक्ष्मण लाल मीणा, ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी लक्ष्मीकांत चोबिसा, सहायक अभियंता अजमेर विद्युत वितरण निगम से अजय सिंह, पशुपालन से डॉ राजु विनके, अतिरिक्त विकास अधिकारी मदन लोहार समेत सरपंच प्रतिनिधि प्रकाश डांगी, पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी नारायण लाल पुरोहित, गिदावल ग्राम विकास अधिकारी श्याम सुन्दर, ग्रामीण और स्टूडेंट मौजूद रहे।

लाइट पोल पर रख-रखाव के दौरान करंट से कर्मचारी झुलसा झटका लगते ही पोल से गिरा, गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती

भीलवाड़ा। विद्युत लाइन पोल पर काम करने के दौरान करंट की चपेट में आने से विद्युत विभाग में लगा संविदा कर्मी झुलस गया। उसे इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर है। मामला मांडल थाना क्षेत्र का है। आज यहां मांडल कस्बे में मांडल के विद्युत ग्रिड पोल पर संविदाकर्मी दुर्गेश सिंह दुल्हावत लाइन के रख रखाव के लिए पोल पर चढ़ा था। इस दौरान लाइन चालू होने से उसे करंट लग गया, जिससे वो झुलस गया और झटका लगते ही पोल से नीचे गिर गया। मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने घटना के



बाद घायल कर्मचारी को शहर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया। डॉक्टर कर्मचारी की हालत गंभीर बता रहे हैं। सूचना मिलने के विद्युत निगम के सहायक अभियंता अनिल पुरोहित सहित अन्य कर्मचारियों ने हॉस्पिटल पहुंचकर घायल की तबीयत की जानकारी ली।

राणा पूजा स्टेडियम में लगाए 150 से अधिक पौधे अभियान के दौरान 3 लाख से अधिक पौधे लगेंगे

रावतभाटा। उपखंड स्तरीय पौधारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ राणा पूजा स्टेडियम परिसर के इंडोर स्टेडियम में समारोह पूर्वक किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि एसडीएम महेश गंगोरिया, एएसपी भगवतसिंह हिंदा ने कहा कि पौधारोपण ही करना जिम्मेदारी नहीं बल्कि इसकी सारसंभाल करना भी जिम्मेदारी है। ग्लोबल वार्मिंग के बीच में आज पर्यावरण का महत्व सभी को पता है। इसलिए इसके महत्व को समझें।



पूर्व प्रधान राधेश्याम गुप्ता, पालिकाध्यक्ष मधुकंदर हाड़ा, प्रधान आरती बाराशा, अतिथि अधिकारी अशोष जैन, विकास अधिकारी सत्येंद्र सिंसोदिया, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजबोरीदेवी, प्रिंसिपल सत्यमा सय्यद, जेसी माली आदि ने संबोधित किया। 2 घंटे चली इस कार्यक्रम में गंभीर से लोगों का हाल बेहाल था। उसके बाद पौधारोपण किया गया। इस मौके पर लगभग 200 पौधे लगाए गए। वनविभाग के रेंजर विनीतमंगल, दिनेशनाथ ने बताया कि सभी विभागों को 100 पौधे निशुल्क वितरण किए गए। रेंजर रावतभाटा की ओर से बड़, पीपल, बेलपत्र, आवला, चुरेल, नीम, करंज आदि पौधों का वितरण किया गया। इस मौके पर तहसीलदार विवेक गरासिया, प्रधान प्रतिनिधि कुशल बाराशा, नगर अध्यक्ष राजेंद्र दशोरा, कनिष्ठ

अभियंता अरविंद तोमर, वनपाल मुकेश पालीवाल, चंद्रभानसिंह, वनकर्मी हमीरागाम, सोनू कुमावत, प्रद्युमनसिंह, पार्षद तन्वी शर्मा, रेखा लोधा, विनिता अग्रवाल, हर्ष जैन, अभिषेक गोखरा, रौनक चौधरी, विष्णु राठौर, विजय गुप्ता, दिनेश सेन, सभी स्कूलों के प्रिंसिपल, प्रशासनिक अधिकारी, पंचायत समिति सदस्य, भाजपा कार्यकर्ता, आमजन मौजूद थे। संचालन कल्पना हाड़ा, ओमप्रकाश राठौर ने किया।

वहीं इस अभियान को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से इस मौके पर बताया गया कि 1 लाख 7 हजार 950 पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया है। जिसमें अभी तक 36 हजार 330 गूठे खोदे जा चुके हैं। 28 हजार 525 पौधे लगाए जा चुके हैं। वहीं यह पौधे 177 स्कूलों में लगाए जा रहे हैं। इसमें हर शिक्षक को 20 एवं हर स्टूडेंट्स को 5 पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया है। पंचायत समिति के विकास अधिकारी ने बताया कि अभी तक 14 हजार 500 पौधे लिए गए हैं। 7 हजार 958 पौधे लगाए जा चुके हैं। वहीं 1 सप्ताह के दौरान टारगेट पूरा कर लिया जाएगा। ओपन बाउंड्री में तार लगाकर 2 से 3 दिन में पौधे लगाए जाएंगे। भैंसरोडगढ़ वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र का अलग से लक्ष्य तय किया गया है। इसके तहत एकलिंगपुरा में 27 हजार, गोपालपुरा रेंज में 7690, आगरा में 118000 पौधे लगाने का लक्ष्य है।

विद्यार्थियों को गुड टच-बैड टच के बारे में जानकारी दी



भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में विद्यार्थियों को गुड टच-बैड टच की जानकारी देने के लिए ऑपरेशन जागृति के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में भैंसरोडगढ़ थानाधिकारी मोहन सिंह शेखावत ने विद्यार्थियों को गुड टच-बैड टच की महत्वपूर्ण जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान थाना प्रभारी शेखावत ने बच्चों को

बताया कि विपरीत परिस्थितियों में किस प्रकार स्वयं को बचाना है। ऐसे ही अन्य बातों को लेकर उन्होंने विद्यार्थियों को समझाया। कहा कि विद्यार्थी किसी भी तरह के मामले और व्यवहार के बारे में स्कूल स्टाफ और अपने अभिभावकों को जरूर बताएं।

जरूरत हो तो पुलिस को भी सूचित करें, ताकि उन्हें सहायता दी जा सके। कार्यक्रम के दौरान स्कूल स्टाफ और विद्यार्थी मौजूद रहे।

आसींद में हेल्थ जागरूकता अभियान 6 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ, लोगों को किया जागरूक

आसींद। आसींद में बंधन बैंक और बंधन कौनगर की ओर से हेल्थ जागरूकता अभियान के तहत दोलतागढ़ में आज 6 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। यह कार्यक्रम भीलवाड़ा जिले के आसींद पंचायत समिति के 28 ग्राम पंचायतों के 137 गांवों में स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने के लिए आयोजित किया गया है। कार्यशाला का शुभारंभ रूपेश शुक्ला, असिस्टेंट मैनेजर, बंधन बैंक और रोहित पारीक, नरेंद्र मीणा, रणजीत और विजेंद्र के साथ घूमने जा रहा है। उन्होंने बताया- रात 8 बजे रोहित पर फायरिंग की सूचना मिली थी। इस पर मौके पर पहुंचे और रोहित को कोटा के निजी अस्पताल ले गए, जहां से उसे एमबीएस अस्पताल रेफर कर दिया। यहां



मामला दर्ज किया है। 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है और पुछताछ की जा रही है।

स्वयंसेवक के रूप में संस्था के साथ जुड़कर गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं, किशोरियों और बालिकाओं को स्वास्थ्य जागरूकता प्रदान करेंगी। कार्यशाला के पहले दो दिनों में, प्रतिभागियों को पोषण, स्तनपान, मौसमी बीमारियों से बचाव और जन जागरूकता जैसे विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। आज के कार्यक्रम में नीतू बैरवा और सोनिया खटौक ने रोल प्ले करने और लाभार्थियों तक स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, कार्यक्रम में बुलबुल सैनी, तारा कटारा, प्रीति पहाड़िया सहित 28 प्रतिभागी मौजूद रहे।

आईटीआई स्टूडेंट की आंख में गोली मारी, मौत : सिर के पीछे वाले हिस्से में जाकर फंसी, दोस्तों के साथ घूमने की कहकर निकला था

कोटा। जमीनी विवाद को लेकर हुए झगड़े में बदमाशों ने आईटीआई स्टूडेंट की आंख में गोली मारी दी। गोली उसके सिर के पीछे वाले हिस्से में फंसी थी। उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बचाव नहीं जा सका। मामला कोटा जिले के कैथून थाना स्थित ताथेड़ गांव का है



कैथून थाना CI धनराज मीणा ने बताया- गोली बाई आंख में घुसकर सिर के पीछे वाले हिस्से में फंसी थी। आज सुबह 11:30 बजे शव का पोस्टमॉर्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। परिजनों ने रोहित मीणा, शरणजीत, लकी, प्रिंस, सोमेश के खिलाफ नामजद और अन्य के खिलाफ

मामला दर्ज किया है। 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है और पुछताछ की जा रही है। दोस्तों के साथ जाने की कहकर गया था : रोहित के चाचा गेंद बिहारी ने बताया- रोहित कोटा में संजय नगर इलाके में स्थित आईटीआई कॉलेज में पढ़ाई करता था। उसका प्लम्बर ड्रेड में दूसरा साल था। वह खेती का काम भी संभालता था। रोहित गुरुवार शाम को गोदलगाहेड़ी खेत पर गया था। वहां से मजदूरों को छोड़ने के लिए आरण्या आया। इसके बाद वह घर आया और कहा कि वह अपने दोस्तों नरेंद्र मीणा, रणजीत और विजेंद्र के साथ घूमने जा रहा है। उन्होंने बताया- रात 8 बजे रोहित पर फायरिंग की सूचना मिली थी। इस पर मौके पर पहुंचे और रोहित को कोटा के निजी अस्पताल ले गए, जहां से उसे एमबीएस अस्पताल रेफर कर दिया। यहां

डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हाथपाई के दौरान हुई फायरिंग : रोहित के दोस्त नरेंद्र मीणा ने बताया- कोटा-बारां हाईवे पर ताथेड़ गांव में श्याम रसोई दाबे पर बाइक खड़ी की और स्कॉर्पियो लेकर डगारिया गांव गए थे। इसमें रोहित, रणजीत और विजेंद्र भी साथ थे। यहां से वापस बाइक लेने श्याम रसोई दाबे पर लौटे तो अचानक रोहित मीणा ने मुझ पर हमला कर दिया। नरेंद्र ने बताया- हम दोनों में आपसे मेरे हाथ पर लट्टू रही थी, इसी दौरान किसी ने पीछे से मेरे हाथ पर लट्टू मार दिया। मेरे सामने खड़े रोहित ने चिखार फायरिंग करने के लिए बोला तो उसके साथ आए युवक ने गोली चला दी। गोली सीधे रोहित की आंख में लगी और वह नीचे गिर गया। रोहित के गोली लगने के बाद बदमाश भाग निकले।

गाय को बचाने के प्रयास में बाइक सवार नीचे गिरा, चोट लगने से मौत

लाठी। लाठी क्षेत्र के गंगाराम की ढाणी के पास दोपहर राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर गाय को बचाने के प्रयास में एक बाइक असंतुलित होकर स्लीप हो गई। हादसे में सिर के बल गिरने से बाइक पर सवार किसान को दर्दनाक मौत हो गई। पाली जिले के अमरपुरा निवासी सोहनलाल(28) पुत्र रामराम अपने परिवार सहित दवाड़ा गांव के रायसिंह सोदा के नलकूप पर पिछले कुछ दिनों से कृषि कार्य करता था। सुबह वह अपनी बाइक की सर्विस करवाने के लिए पोकरण गया था। बाइक सर्विस करवाने के बाद दोपहर को दवाड़ा गांव स्थित नलकूप पर लौट रहा था। इस दौरान गंगाराम की ढाणी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर बाइक के आगे अचानक गाय आ

गई। इस दौरान बाइक चालक द्वारा गाय को बचाने का प्रयास किया गया। ऐसे में बाइक असंतुलित होकर सड़क से नीचे उतरते हुए स्लीप हो गई। सिर के बल गिरने से बाइक चालक किसान सोहनलाल ने मौके पर दम तोड़ दिया।



पूजा खेडकर के बाद... पूर्ण आईएसएस अधिकारी अभिषेक भी विवादों में

नई दिल्ली। ट्रेनी आईएसएस अधिकारी पूजा खेडकर के निजी गाड़ी पर लाल-नीली बत्ती लगाने और कथित फर्जी प्रमाणपत्र को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। इसके चलते उन्हें पुराने से वाशिम भेज दिया गया है। इस बीच अब एक अन्य पूर्ण नौकरशाह के विकलांगता मानदंड में चयन पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल, यूपी काडर के 2011 बैच के पूर्ण आईएसएस अधिकारी अभिषेक सिंह ने पिछले साल अभिनेता बनने के लिए इस्तीफा दे दिया था। अपने डांस और जिम वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अभिषेक आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं। सिंह ने यूपीएससी चयन प्रक्रिया में रियायत पाने के लिए चलने-फिरने में अक्षम होने का दावा किया था। सिंह द्वारा साझा वीडियो पर कई यूजर्स ने नौकरशाही चयन प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की। वहीं इन आरोपों पर अभिषेक ने जवाब देकर कहा कि मुझे आरक्षण का समर्थन करने के लिए निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि, मैं किसी आलोचना से प्रभावित नहीं होता, लेकिन यह पहली बार है जब मैं अपने आलोचकों को जवाब दे रहा हूँ क्योंकि मेरे समर्थकों ने मुझसे ऐसा करने के लिए कहा था। जब से मैंने आरक्षण का समर्थन करना शुरू किया है, आरक्षण विरोधियों ने मुझे निशाना बनाया है। वे मेरी जाति और नौकरी पर सवाल उठाते हैं। मैं आपको बता दूँ कि मैंने कड़ी मेहनत और साहस से सब कुछ हासिल किया है, आरक्षण के द्वारा नहीं। मेरा मानना है कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण आबादी के हिसाब से होना चाहिए और मैं इस दिशा में काम करूँगा। अगर आपको लगता है कि आपके पास प्रतीति है, तब सरकारी नौकरियों के लिए प्रयास करना बंद करें और व्यवसाय, खेल या अभिनय में आगे बढ़ें। आईएसएस अभिषेक सिंह जौनपुर के रहने वाले हैं। उन्हें अभिनय शौक है। अभिषेक के पिता वृषाणकर सिंह उत्तर प्रदेश में आईपीएस थे। अब वे सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

दो नाबालिगों की आखें फोड़ीं, जीभ और सीने पर चाकू मारकर की हत्या

- घटना से आक्रोशित लोगों ने लगाया जाम, परिजनों को बलि देने का शक

पटना। बिहार के पटना में सोमवार सुबह दो नाबालिग की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक एक पेट्रोल पंप के पास स्थित गैराज के पास पानी भरे गड्ढे में दोनों शव बरामद किए गए हैं। दोनों के हाथ-पैर बंधे हुए थे शवों पर जखमों के निशान थे। एक की उम्र 11 साल और दूसरे की 12 साल के करीब है। सुबह मौनंग वॉक करने लोग निकले थे दोनों का शव देखकर हैरान गए तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। जानकारी मिलते ही दोनों के परिजन और स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंच गए। घटना से आक्रोशित लोगों ने उपनगर-30 जाम कर दिया। आगजनी कर हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। दो नाबालिग की पहचान गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के सरिस्ताबाद मोहल्ले के रहने वाले 12 वर्षीय विवेक कुमार और 11 वर्षीय प्रयुष कुमार के रूप में हुई है। विवेक चौथी क्लास में तो प्रयुष छठी क्लास में पढ़ रहा था। परिजनों का कहना है कि दोनों के मायबहू होने की सूचना रात में गर्दनीबाग थाने में की थी। शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई एवशन नहीं लिया। विवेक के पिता विनोद कुमार ने आरोप लगाया है कि बच्चों की आखें फोड़ी गईं हैं। जीभ और सीने पर भी चाकू से वार किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर यह भी संपादना जाता है कि पहले बच्चों के साथ मारपीट की गई होगी और फिर हत्या कर पानी में शव को फेंक दिया होगा। जहां से शव मिले हैं वहीं पास में एक कंपनी का प्रोजेक्ट चल रहा है। परिजनों ने आरोप लगाया कि कई दिनों से प्रोजेक्ट का काम रुका हुआ था। उसे शुरू करने के लिए बच्चों की बलि दी गई है। बच्चों की हत्या करके शवों को खड़ा फेंका गया है। इस मामले में अभी तक पुलिस की ओर से कोई बयान नहीं आया है। हालांकि पटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। पुलिस लोगों को समझाने का प्रयास करती रही।

मुह्रम नहीं तो कांवड़ यात्रा, रामलीला आदि भी नहीं होनी चाहिए

- सीएम योगी के बयान पर परसल लॉ बोर्ड के फारुकी ने दी सख्त प्रतिक्रिया

लखनऊ। यूपी सीएम योगी के मुह्रम के संबंध में दिए गए बयान पर बवाल मच गया है। सामान्य नागरिक सहिता पर ओल इंडिया मुस्लिम परसल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) के सदस्य कमाल फारुकी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है अगर मुह्रम नहीं होगा, तो कांवड़ यात्रा, रामलीला आदि भी नहीं होनी चाहिए। सड़क पर कोई भी धार्मिक प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। रामलीला को भी बंद कर देना चाहिए। सबके लिए अलग-अलग नियम नहीं हो सकते हैं। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सब समान हैं। कमाल फारुकी ने कहा कि हमें यूसीसी की भी हाल में स्वीकार नहीं है और वे इस कानून को कोर्ट में चुनौती देंगे। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों के परसल कानून में किसी भी तरह का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा यूपीकॉम सिविल कोड संविधान का हिस्सा नहीं है, इसलिए वे नहीं स्वीकार नहीं है। फारुकी ने कहा कि संविधान हमें अपने धर्म का अनुसरण करने की पूरी आजादी देता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें संविधान से परसल लॉ मिला है, जो हमारे कुरुआन ने बताया है, उसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं इसके खिलाफ बने कानून को हम चुनौती देंगे। उन्होंने तलाक के बाद मुस्लिम महिलाओं को गुजारा-भते देने के कोर्ट के फैसले पर कहा कि इसके लिए हमारी वर्किंग कमेटी की बैठक हुई है इसमें चर्चा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले पर किस तरह से प्रतिक्रिया दी जाएगी।

किशनगंज में अवैध तरीके से बॉर्डर क्रॉस कर रहे तीन को पकड़ा

किशनगंज। भारत बांग्लादेश सीमा पर रविवार को तीन बांग्लादेशी घुसपैटियों को बीएसएफ के जवानों ने पकड़ा। बीएसएफ की 72वीं बटालियन के बीओपी बोर्न के जवानों ने तीनों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार तीनों लोग भारतीय सीमा से बांग्लादेश में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। गिरफ्तारियों से जब पूछताछ की गई तो तीनों बांग्लादेशी नागरिक निकले। बीएसएफ माल निरीक्षक सुर्यकांत शर्मा ने जानकारी देहू एतयाय कि तीनों घुसपैटियों की पहचान अब्दुल रहीम का बेटा रोजीउल (31), अकबर अली का बेटा मो फरीद (25), मो शाह जमाल का बेटा मो सैमुल (18) के रूप में हुई है। तीनों ही बांग्लादेश के टाकुरगांव के रहनेवाले हैं। गिरफ्तार घुसपैटियों के पास से 50 बोटल फेंसीडिल, कई निजी सामान, भारतीय रुपय में 8 हजार आदि बरामद किया गया। गिरफ्तार सभी आरोपियों से बीएसएफ पूछताछ कर रही है।

टगी का नया तरीका बन सकता है ई-नोटिस, सरकार ने किया सतर्क

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने ईमेल उपयोगकर्ताओं को दिल्ली पुलिस साइबर अपराध और आर्थिक अपराध, केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो (सीआईआईबी), खुफिया ब्यूरो और दिल्ली के साइबर प्रकोष्ठ के नाम, हस्ताक्षर, टिकट और लोगों वाले धोखाधड़ी के ईमेल के बारे में सचेत करते हुए एक सार्वजनिक परामर्श जारी किया। चार जुलाई को जारी परामर्श के अनुसार, इन ईमेल के साथ संलग्न पत्र में ईमेल प्राप्तकर्ताओं के खिलाफ बाल पोर्नोग्राफी, बाल यौन शोषण, साइबर पोर्नोग्राफी, अश्लीलता के आरोप लगाए जाते हैं। इसमें कहा गया है कि टग ऐसे फर्जी ईमेल भेजने के लिए अलग-अलग ईमेल पते का इस्तेमाल करते हैं। इसमें कहा गया है, ऐसे किसी भी ईमेल के प्राप्तकर्ता को इस धोखाधड़ी के प्रयास के बारे में पता होना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय की साइबर अपराध इकाई ने रविवार को कहा कि ईमेल पर किसी सरकारी कार्यालय से संदिग्ध ई-नोटिस मिलने पर लोगों को इसमें लिखे अधिकारी के नाम की प्रामाणिकता की इंटरनेट पर जांच करनी चाहिए और संबंधित विभाग को फोन करना चाहिए। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (4सी) ने एक सार्वजनिक विज्ञापन में कहा कि उपयोगकर्ताओं को किसी सरकारी ई-नोटिस की आड़ में भेजे गए फर्जी ईमेल को लेकर सतर्क रहना चाहिए। विज्ञापन में आगाह किया गया है कि यह कोई टग हो सकता है जो लोगों को साइबर धोखाधड़ी का शिकार बना सकता है। 14सी ने ऐसे ईमेल पर विलक करने या उनका जवाब देने से पहले जवाबी उपाय सुझाए हैं। यह जांच कर कि क्या ईमेल किसी प्रामाणिक सरकारी वेबसाइट से आया है जिसके अंत में जीओवी डोट इन है, ईमेल में नामित अधिकारियों के संबंध में इंटरनेट पर जानकारी खंगालें और प्राप्त ईमेल को सत्यापित करने के लिए उल्लिखित विभाग को फोन करें। आज नजता को सूचित किया जाता है कि संलग्नक के साथ ऐसे किसी भी ई-मेल का जवाब नहीं दिया जाना चाहिए और ऐसे मामलों की सूचना निकटतम पुलिस थाने/साइबर पुलिस थाने को दी जा सकती है।

राज्यसभा में भाजपा का दबदबा हुआ कम, अब कैसे पास करवाएगी बिल

नई दिल्ली (एजेंसी)। केवल लोकसभा में ही नहीं, राज्यसभा में भी भाजपा और एनडीए का संख्या बल कम हुआ है। राज्यसभा में बीजेपी के चार मनोनीत सदस्य शनिवार को रिटायर हो गए। इसके साथ ही उच्च सदन यानी राज्यसभा में बीजेपी की ताकत घटकर 86 और एनडीए की 101 रह गई है। 19 सीटें खाली होने की वजह से राज्यसभा में फिलहाल सदस्यों की संख्या 226 है। इसका जवाब है कि भाजपा अब भी मजबूत स्थिति में है। नंबर गेम में अब भी वह आगे ही है। एनडीए के पास अब भी सात गैर-राजनीतिक मनोनीत सदस्यों, 2 निर्दलीय और एआईडीएमके और वाईएसआरसीपी जैसे दोस्ताना दलों के समर्थन से आगामी बजट सत्र में अहम कानून पारित करवाने की संख्या है। मगर दूसरों पर निर्भरता कम करने के लिए मनोनीत कैटेगरी के तहत जल्द से जल्द रिक्त पदों को भरना अहम होगा।



राज्यसभा के लिए मनोनीत होने के बाद इन्होंने औपचारिक रूप से खुद को बीजेपी के साथ जोड़ लिया था। मनोनीत कैटेगरी में एक और राज्यसभा सदस्य गुलाम अली हैं, जो बीजेपी का हिस्सा हैं। वे सितंबर 2028 में रिटायर होंगे। आने वाले महीनों में इन 11 सीटों पर होने वाले चुनाव में संभवतः आठ सीटें एनडीए और तीन सीटें इंडिया गठबंधन के कब्जे में जा सकती हैं। कांग्रेस को तेलंगाना से एक सीट मिलेगी, जिससे पार्टी की संख्या राज्यसभा में 27 हो जाएगी। राज्यसभा में अपना विपक्ष का पद बनाए रखने के लिए कांग्रेस को जितनी

सीटों की जरूरत है, यह उससे दो अधिक है। इसलिए कांग्रेस की आवाज राज्यसभा में बुलंद होगी। हालांकि, भाजपा अथवा एनडीए को राज्यसभा में आगामी बजट सत्र में बिल पास करवाने में बहुत अधिक परेशानी नहीं होगी।

दरअसल, राष्ट्रपति सरकार की सिफारिश पर राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। मौजूदा सदन में उनमें से सात ने खुद को गैर-राजनीतिक (बीजेपी का हिस्सा नहीं) रखा, मगर ऐसे सदस्य कानून पारित कराने में हमेशा सरकार का ही साथ देते हैं। मौजूदा वक्त में राज्यसभा में 19 सीटें खाली हैं। इनमें जम्मू-कश्मीर और मनोनीत कैटेगरी से चार-चार और आठ अलग-अलग राज्यों (असम, बिहार और महाराष्ट्र से दो-दो और हरियाणा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान और त्रिपुरा से एक-एक) से 11 सीटें शामिल हैं। लोकसभा चुनाव की वजह से इन 11 सीटों में से 10 सीटें पिछले महीने खाली हुईं। जबकि एक सीट भारत राष्ट्र समिति के सदस्य के केशव राव के इस्तीफे के कारण खाली हुई थी। केशव राव बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए।

मुस्लिम परसल लॉ बोर्ड ने कहा: तलाकशुदा महिलाओं के भरण-पोषण का फैसला स्वीकार नहीं करेंगे

नयी दिल्ली। (एजेंसी)। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला को सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पूर्व पति से भरण-पोषण पाने का अधिकार है। इस पर मुस्लिम परसल लॉ बोर्ड का कहना है कि यह फैसला उन मुस्लिम महिलाओं के लिए मुश्किल खड़ी करेगा, जो अपने दम्पन रिश्ते से सफलतापूर्वक बाहर आ चुकी हैं। बोर्ड ने जोर देकर कहा कि यह मानवीय तर्क के साथ अच्छा नहीं है कि तलाक हो जाने के बाद भी व्यक्ति को पूर्व पत्नियों की जिम्मेदारी उठाने के लिए कहा जा रहा है। वे हमें स्वीकार नहीं है। इसका फैसला ऑल इंडिया मुस्लिम परसल लॉ बोर्ड की बैठक में लिया गया।



फैसले को वापस कराने के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं। गौरतलब है कि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला को सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पूर्व पति से भरण-पोषण पाने का अधिकार है।

मामले पर चर्चा करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम परसल लॉ बोर्ड वर्किंग कमेटी ने इस बात पर जोर दिया है कि उल्लेख किया था कि सभी संभावित कर्मों में से अल्लह की दृष्टि में सबसे घृणित तलाक है। इसलिए हर कोशिश करके शादी को जारी रखना ही उचित है। बोर्ड ने आगे कहा कि अगर इसके बावजूद शादी को बरकरार रखना मुश्किल हो जाता है तो ईसाईयत की भलाई के लिए तलाक का उपाय बताया गया है। बोर्ड ने अपने प्रेसीडेंट को यह अधिकार दिया कि वह सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को वापस करने के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं। इसके लिए वह कानूनी, संवैधानिक या लोकतांत्रिक, कोई भी रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। बोर्ड ने यह भी कहा कि वह इस मामले को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष से बात

करेगी। इसके अलावा बोर्ड ने यूसीसी पर भी अपनी राय जाहिर की। बोर्ड ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को चुनौती देने का संकल्प लिया और अपनी कानूनी समिति को एक याचिका दायर करने का निर्देश दिया। बोर्ड ने कहा कि हालिया लोकसभा चुनाव के परिणामों से भी संकेत मिले हैं कि लोग सरकार के कदमों से सहमत नहीं हैं।

मुस्लिम परसल लॉ बोर्ड ने कहा कि यह फैसला उन मुस्लिम महिलाओं के लिए मुश्किल खड़ी करेगा, जो अपने दम्पन रिश्ते से सफलतापूर्वक बाहर आ चुकी हैं। बोर्ड ने जोर देकर कहा कि यह मानवीय तर्क के साथ अच्छा नहीं है कि तलाक हो जाने के बाद भी व्यक्ति को पूर्व पत्नियों की जिम्मेदारी उठाने के लिए कहा जा रहा है। बोर्ड ने इस बात पर जोर दिया कि भारत जैसे बहु-धार्मिक देश में, धार्मिक संस्थाओं को अपने स्वयं के कानूनों का पालन करने का अधिकार है, जैसे मुसलमानों के लिए शरिया एप्लिकेशन अधिनियम-1937। बोर्ड ने ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही इंदगाह से संबंधित नए विवादों पर विचार करने के लिए निचली अदालतों को आलोचना की। इसने सुप्रीम कोर्ट से 'पूजा स्थल अधिनियम, 1991' को बरकरार रखने और विवादास्पद मस्जिदों की रक्षा करने का आग्रह किया, साथ ही उन्हें ध्वस्त करने या बदलने के किसी भी प्रयास के प्रति आगाह भी किया।

कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की केस रद्द करने की याचिका

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट से कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, शीर्ष अदालत ने डीके शिवकुमार की आय से अधिक संपत्ति के कथित मामले में उनके खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दत्त मामले को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति एसजी राम की पीठ ने कहा कि वह कर्नाटक उच्च न्यायालय के ऑफिस में हस्तक्षेप करने की इच्छुक नहीं है। पीठ ने कहा, 'माफ करें। खारिज कर दिया गया।'

इसके बाद डीके शिवकुमार ने कहा कि भी घोटाले भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाए गए हैं। भाजपा का कार्यकाल घोटालों का जनक है, यही कारण है कि जनता ने उन्हें बाहर कर दिया है। हम सब कुछ साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। वे इसे पचा नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके नाम सामने आ जाएंगे। सीबीआई ने सितंबर 2020 में कांग्रेस नेता के खिलाफ एफआईआर दाय की, जिसमें आरोप लगाया गया कि शिवकुमार ने 2013 और 2018 के बीच अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से

मायावती की हरियाणा में भाई-भतीजे को आजमाने की तैयारी

लखनऊ (एजेंसी)। मायावती अपने सबसे बड़े 'बर' उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी हार के पश्चात बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी में बहुत कुछ बदल दिया है। लगता है डोर अब 'बैक डोर' से पार्टी की कमान संभालेंगी और उनके भाई आनंद कुमार और भतीजा आनंद आकाश फंट में आकर बहन मायावती के सियासी अस्पानों को पूरा करेंगे। इसकी शुरुआत हरियाणा से होती दिख रही है। इन दोनों नेताओं का हरियाणा में स्टूडिओ रेट अच्छा रहा तो बहन मायावती यूपी के लिए भी इनके 'दरवाजे' खोल सकती हैं। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में बसपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार और नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की भी परीक्षा होगी। लंबे अरसे के बाद मायावती के भाई आनंद कुमार राजनीति में देवारा सक्रिय हुए हैं, तो

विधानसभा चुनाव के प्रचार की शुरुआत के बाद मायावती की इनेलो नेताओं के साथ संयुक्त रैलियों का खाका तैयार करने का जिम्मा आकाश आनंद को दिया गया है। यदि आकाश की रणनीति को सफलता मिलती है तो यूपी में उनकी नई सियासी पारी का आगाज हो सकता है।

बता दें कि हरियाणा में बसपा के संस्थापक कांशीराम की चौधरी देवीलाल से मित्रता रही है। पहले भी दोनों दल गठबंधन करके चुनाव लड़ चुके हैं। लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद बसपा को हरियाणा चुनाव से खाली उम्मीदें हैं। जानकारों की मानें तो मायावती ने इसी वजह से आनंद कुमार और आकाश को हरियाणा चुनाव की कमान सौंपी है ताकि दोनों की सियासी जमीन को मजबूत किया जा सके।

वहीं दूसरी ओर उनके बेटे आकाश आनंद ने भी लोकसभा चुनाव के बाद फिर से वापसी की है। सूत्रों की मानें तो बसपा अध्यक्ष मायावती ने कांशीराम के जमाने से चली आ रही इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) और बसपा की दोस्ती को

आगे बढ़ाने का जिम्मा दोनों को सौंपा है। यही वजह है कि इनेलो के साथ गठबंधन की औपचारिक घोषणा भी आनंद कुमार और आकाश आनंद की मौजूदगी में की गयी। हरियाणा चुनाव में बसपा के 37 प्रत्याशियों के चयन का जिम्मा भी उन्हें ही सौंपा गया है।

अनंत की शादी में बम की धमकी, संदिग्ध को तलाशने में जुटी पुलिस

मुंबई। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में बम की धमकी देने वाले की तलाश तेज हो गई है। पुलिस उस एक्स हैडल के बारे में जानकारी जुटा रही है, जिससे यह धमकी दी गई थी। सोशल मीडिया हैडल एक्स पर एक संदिग्ध पोस्ट की गई थी, जिसमें 'अंबानी की शादी में एक बम' लिखा था। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक मुंबई पुलिस को इस बारे में जानकारी थी, लेकिन यह एक हॉक्स था। एक्स पर संदिग्ध पोस्ट की गई थी। इसमें लिखा था, 'मेरे दिमाग में एक बेहद शर्मनाक ख्याल आया है। अगर अंबानी की शादी में एक बम आ जाए, आधी दुनिया इधर की उधर हो जाएगी। कई अरब डॉलर सिर्फ एक पिन कोड में हैं। इस पोस्ट के बारे में जानकारी मिलते ही मुंबई पुलिस पूरी तरह से सतर्क हो गई थी। पुलिस ने कोई एफआईआर तो नहीं दर्ज की है, लेकिन 13 जुलाई को एक्स पर यह पोस्ट करने वाले शख्स की तलाश तेज है। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि अखिर इसके पीछे शख्स का मकसद क्या था। इस पोस्ट को देखते हुए पुलिस ने वैडिंग वेन्यू पर सुरक्षा इंतजाम काफी तगड़े कर रखे थे। बीकेसी के अलावा रिसेशन वाली जगह पर भी सिक्कीरिटी टाइट थी। पुलिस के सूत्रों ने बताया कि इस मैसेज को तो वेस हैक्स के तौर पर लिया गया है, लेकिन सोशल मीडिया पोस्ट देखने वाली टीम मामले की गहराई से छानबीन करेगी। पुलिस को शनिवार को इस पोस्ट के बारे में पता चला था।

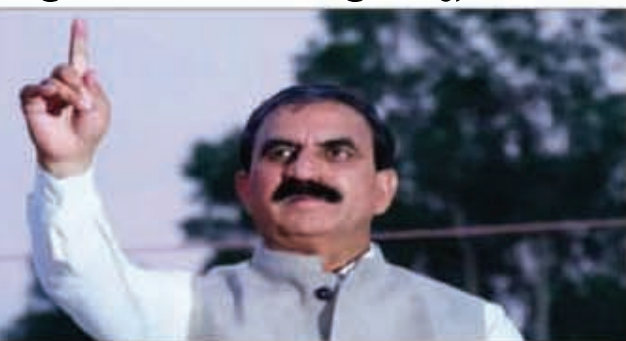
आगे बढ़ाने का जिम्मा दोनों को सौंपा है। यही वजह है कि इनेलो के साथ गठबंधन की औपचारिक घोषणा भी आनंद कुमार और आकाश आनंद की मौजूदगी में की गयी। हरियाणा चुनाव में बसपा के 37 प्रत्याशियों के चयन का जिम्मा भी उन्हें ही सौंपा गया है।

कांग्रेस के दो योद्धाओं ने बदल दिया हिमाचल का समीकरण, सुरक्षित हो गई सुक्खू सरकार

शिमला (एजेंसी)। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की तीन सीटों पर उपचुनाव का रिजल्ट आने से सुक्खू सरकार ने राहत की सांस ली है। यहां दो सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली है। जबकि एक सीट भाजपा के पाले में गई है। बीते पांच महीनों से सुक्खू सरकार पर चला आ रहा संकट टल गया है। हालांकि, क्या अब भी बीजेपी फिर से सुक्खू सरकार की सत्ता का खेल बिगाड़ सकती है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुक्खू की सरकार से राजनीतिक संकट दूर हो गया है। यहां साल 2022 में हुई विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 40 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी और बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया था। इसके ठीक डेढ़ साल बाद राज्यसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस 6 विधायक

बागी निकल गए। उन्होंने पार्टी के खिलाफ वोट कर दिया और बीजेपी कैडेट्स हर्ष महाजन को वोट दिया। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी डॉ अंधिषेक मनु सिंघवी चुनाव हार गए। बागी विधायकों ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी थी। इसके बाद बीजेपी के पास कुल 34 विधायक हो गये थे। फिर लोकसभा चुनावों के साथ ही इन छह सीटों पर उपचुनाव हुआ। इसमें कांग्रेस 4 सीटों पर जीत गई थी। जिसके बाद कांग्रेस विधायकों की संख्या 38 हो गई थी। बीजेपी दो सीटें जीत गई थी। उनके विधायकों की संख्या भी 27 हो चुकी थी। एक बार फिर सियासत लड़ गई जब तीन निर्दलीय विधायकों

जाएंगे। हालांकि सीएम सुक्खू गृह जिला हमीरपुर की सीट पर हार गए। यहां से कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पेंद्र वर्मा की हार हुई है। इससे सीएम सुक्खू की लोकप्रियता पर सवाल उठ रहे हैं। बागी विधायकों ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी थी। इसके बाद बीजेपी के पास कुल 34 विधायक हो गये थे। फिर लोकसभा चुनावों के साथ ही इन छह सीटों पर उपचुनाव हुआ। इसमें कांग्रेस 4 सीटों पर जीत गई थी। जिसके बाद कांग्रेस विधायकों की संख्या 38 हो गई थी। बीजेपी दो सीटें जीत गई थी। उनके विधायकों की संख्या भी 27 हो चुकी थी। एक बार फिर सियासत लड़ गई जब तीन निर्दलीय विधायकों



ने विधानसभा से इस्तीफा दिया। इसी वजह से तीन सीटों पर उप चुनाव हुआ। इसका रिजल्ट बीते शनिवार को आया। जिसमें कांग्रेस ने दो